



- | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ★ कैसा, कौन-सा राष्ट्र हित? कमीशन सर्वोपरि | ★ अधिकांश निजी व शास. शिक्षण संस्थाएं जालसाजों के अड़े | ★ मुख्यमंत्री की घोषणाओं व दुहाई पर पलीता | ★ सूचना अधिकार अधि. 05 का बलात्कार | ★ नियंत्रक खाद्य व उपसंचालक, नापतौल से खुला सपोर्ट | ★ रिजर्व बैंक की गृहऋण दरों पर ब्याज दर बढ़ाने की नौटंकी |

मनमोहन की नौटंकी-परमाणु समझौते का सच

मात्र कमीशन के बदले राष्ट्र को गिरवी करने का षड्यंत्र

नई दिल्ली। 3 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने स्पष्ट कर दिया कि परमाणु समझौते के बाद भारत परमाणु बमों की परीक्षण नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेगा तो तत्काल उसकी आपूर्ति रोक दी जाएगी।

समय माया इस सत्यता का लगातार अपनी भ्रष्टाचार की साइटों पर 2007 से प्रकाशित कर रहा था, जैसा हम लिख रहे थे बिल्कुल वैसा ही सच सामने प्रकट हुआ है। कुछ सच प्रकट होना शेष है सारी कारिस्तानी कमीशन की थी। यह भ्रष्ट मनमोहन को तो शुरू से ही मालम था, फिर भी सरकार को दांव पर लगाकर भी समझौता हस्तांतरित किया गया, जबकि परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) का शिगूफा केल नौटंकी का हिस्सा और विशुद्ध बकवास है, तो यूरोनियम, थोरियम, प्लूटोनियम भारत व अन्य विश्व के



आखिर समय माया का सच सामने आ ही गया

राष्ट्रों से आयात करते हैं। यह तो स्पष्ट है कि भारत में भी यूरोनियम, थोरियम, प्लूटोनियम के अयस्कों के भारी भंडार कई प्रदेशों में हैं। तो फिर आयात क्यों? साथ ही अमेरिका जैसे धूर्त, संकर मानवों के साथ समझौता क्यों और कैसा स्पष्ट है कि उन धूर्तों का ये मायाजाब केवल कमीशन बांटकर भारत को परमाणु बमों के परीक्षण निर्माण से रोकने का है।

सीधा सा यक्ष प्रश्न यह है कि 120 करोड़ की आबादी की प्रतिभाओं से विश्व के राष्ट्र तरक्की करते हैं। 120 करोड़ के देश को अनुदानों की भीख आकरि बांटते हैं, तो क्यों? इसे आखिर कब तक भिखारी बने रहना चाहिए, हमारे लोहे से जो मिट्टी के भाव खरीदकर प्लेटिनम की कीमत से ज्यादा महंगा बेचकर हमें ही लौटाते हैं तो हम क्यों सब कुछ नहीं शेष पेज 2 पर



समय माया का सच, नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार

चीनी इशारे पर बिहार में बाढ़ का तांडव

भारत की वर्तमान केंद्रीय राजनीति में जिन भ्रष्टों मक्कारों, निकमें गिद्ध मुखरेस, देश बेचु, राजनीतिज्ञों की फौज बैठी हैं, उन्हें अपने लुटने, खाने के सामने राष्ट्र और राष्ट्र की जनता का न, तो हित दिख रहा है, न ही नेपाल में बनी कम्युनिस्टों की सरकार जो चीनी कठपुतली बन नाच रही है और भविष्य में नाचेगी जिसकी घोषणा भी समय माया ने अपने फरवरी-मार्च के अंकों में कर दी थी, के दुष्कृत्यों के परिणामस्वरूप बिहार के 4-5 जिलों में बरपे कोसी नदी के बाढ़ का तांडव जिसमें 1500 से ज्यादा गांवों में 15 दिन से 10-15 फीट तक पानी भरा रहा है बाढ़ में 1 से 3 लाख मारे जा चुके हैं, कम से कम 5 लाख से ज्यादा मवेशी मर चुके हैं, नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय आपदा बता देने से पेट नहीं भरता है, वहां पर किए जा रहे सेना के प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह तो शुरूआत है। जहां नेपाल के पानी लगातार छोड़ने से यह भयावह स्थिति बनी है। वहां पर इस बाढ़ के बाद चीनी हथियारों, चीनी तेल साबुन से लगाकर हर शेष पेज 2 पर

2 लाख से ज्यादा की मौत 80 लाख बेघर

अमेरिकी गुंडे के गुलाम नाटो जार्जिया की आड़ में रूस को घेरने की तैयारी में

अमेरिकी साम्राज्य चाटी नीतियां कर रही तीसरे विश्व युद्ध का आह्वान

जार्जिया को अमेरिकी और नाटो की शह क्या मिली उसने आस्ट्रिया पर कब्जे की तैयारी कर दी बदले में रूस ने जार्जिया पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण के तुरंत बाद अमेरिका और नाटो ने चिल्लाना और रूस को धमकाना शुरू कर दिया। जार्जिया को अमेरिकी गुंडे और नाटो फौजों का समर्थन का मूल उद्देश्य है। रूस जैसे महाशत्रु को जो कि अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों को एक खुली चुनौती बना हुआ है, को ही प्रत्यक्ष रूप से धमकाना है।

जार्जिया 20 वर्ष पहले तक रूस का ही एक राज्य हुआ करता था, जहां सुखोई जैसे विमानों का निर्माण होता था, अमेरिका द्वारा रूसी सोवियत गणराज्य को 26 टुकड़ों में बांटकर उसकी उस चुनौती को अपनी जालसाजियों, चालकियों, छलकपट से ध्वस्त अवश्य कर दिया, इसके विपरीत रूस की आर्थिक रूप से पूरी व्यवस्था चौपट करने के बाद वह अपनी व्यवस्था को पिछले 10 वर्षों में गाड़ी पर ले आया और पुनः अमेरिकी गुंडे और उसके गुलाम नाटो राष्ट्र के लिए चुनौती बन खड़ा हो चुका है। अब अमेरिका रूस से अलग हुए राज्यों को धन बल और अन्य प्रकार के सहयोग का लालच देकर उन्हें रूस के विरुद्ध खड़ा करने और



सीधे दो-दो हाथ करने के लिए उकसा रहा है। जार्जिया उसका तात्कालिक ज्वलंत प्रमाण है। रूस ने उस पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने उसे तीन सहायता के नाम पर जहाज भेज दिए। समय माया की इन पर सतत निगाह थी और हमने पूरी दुनिया में इन तीन सहायता के जहाजों के नाम पर भेजी जा रही युद्ध सामग्री, गोला बारुद, शेष पेज 2 पर

परमाणु समझौते में कमीशन बाजी का खेल

नई दिल्ली। आखिर परमाणु समझौते के लिए जनवरी 06 से जो भारत का धूर्त प्रधानमंत्री मनमोहन और उसकी अम्मा यूरोपियन एजेंट सोनिया सत्ता को दांव पर लगाकर भी इस समझौते के पीछे पड़े थे तो आखिर इतना उतावनापन क्यों था।

समय माया लगातार अपने प्रकाशनों में लिख रहा था कि सारा खेल कमीशन का है जो सी.एन. की बीबीसी की साइटों से खोजा गया तो मालूम पड़ा कि यह अ. डालर 150 अरब अर्थात् भारतीय रुपए 6000 अरब का सौदा है, जिसमें 10% प्रधानमंत्री मनमोहन और 10 % शेष पेज 2 पर

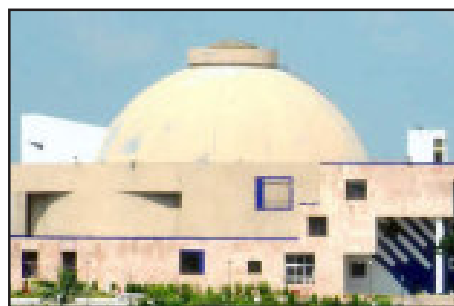
रु. 1200 अरब सोनिया और मनमोहन के अमेरिकी डालर 150 अरब में 10% बुश

म.प्र. विधानसभा चुनावी शृण-०८, मतदाता जाग्र

कांग्रेस में मुख्यमंत्री के अनेक द्वावेदार

म.प्र. में आने वाले नवंबर-दिसंबर 08 में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ सामने आकर प्रकट होने लगे हैं, कुछ पीछे से मंच तैयार करने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री होने के सहारे प्रदेश में अपने बड़े-बड़े विज्ञापन समाचार पत्रों में छपवाकर दावेदारी सिद्ध करने में लगे हैं। इन सबके विपरीत कुछ ऐसे घाघों का टोला भी जो मंच तैयार होने पर एकदम प्रकट होगा, जिसमें दिग्गीदानव विशेषज्ञ है। हाल फिलहाल चुनावों की तिथि की घोषणा होने तक भारी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे।

यूरोपीय जासूस केंद्रीय राजनीति की वर्तमान अम्मा सोनिया गांधी के दिल की पहली पसंद उसके स्वर्गीय प्रेमी माधव का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के लिए हैं। जिन्होंने स्व. राजीव गांधी का अंत्येष्टि



कार्यक्रम देखा होगा उन्हें याद होगा कि यह यूरोपीय राष्ट्रों की व्यावसायिक राजनीतिज्ञ प्रतिनिधि और इटली के पोप की चेली अपने पति राजीव की अंत्येष्टि में काला चश्मा लगाए यहाँ-वहाँ ताकती रही। उसकी व उसकी बेटी प्रियंका की आंख में एक आंसू नहीं था, परन्तु माधवराव की अंत्येष्टि में ये मां-बेटी दोनों झार-झार रोई थी अस्तु। अपने प्रेमी के बेटे को कौन उच्चतम पद देना नहीं चेहा इसलिए ज्योतिरादित्य म.प्र. की राजनीति में केंद्रीय राज्यमंत्री बनकर अपना

मैदान पकड़ने की तैयारी कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने छिदवाड़ा सम्मेलन इसी दृष्टिकोण से बुलवाया, परन्तु वहां जूतम पैजार हो गई, पर यह तो भारतीय राजनीति की परंपरा है। उसमें भी कांग्रेस आगे हो, यह तो लोकप्रियता का पैमाना है, शेष पेज 2 पर

संपादकीय

सुरक्षा, क्रीम-शा राष्ट्र हित?

कमीशन सर्वोपधि

इस महान राष्ट्र की गरिमामयी परंपराएं शायद इतिहास और वर्तमान में न कभी थी और न अब हैं, न कभी रहेगी। इस राष्ट्र की हजारों वर्ष की गुलामी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमने अपने स्वार्थी की खातिर विदेशियों का खूब स्वागत किया और गुलामी भोगी, इसके विपरीत न हमने इतिहास से सबक सीखा न वर्तमान में सुधरे न भविष्य में अपने स्वार्थी की खातिर राष्ट्र हितों की सुरक्षा करने को तैयार है उन्हें ही वर्तमान भ्रष्ट प्रधानमंत्री ने अपने कमीशन के लिए राष्ट्र के चलते परमाणु कार्यक्रमों को पीछे धकेलकर कमीशन के लिए अमेरिका जैसे विश्व के गुंडे को अपनी सुरक्षा सौंपकर परमाणु करार के लिए देश की सत्ता को भी दांव पर लगाया, सत्ता जाते देख उसका धूर्त मक्कार और उसके गिरोह ने सांसदों की खरीद-फरोख्त कर सरकार बचाकर भी समझौता कर अपना रु. ६०० करोड़ का कमीशन जरूर पक्का किया।

जब राष्ट्र का प्रधानमंत्री ही राष्ट्र की सुरक्षा को दरकिनार कर अपना कमीशन डकार बैंक बैलेंस मजबूत करने में लगा हो तो फिर क्या न्यायाधीश, क्या मंत्री, क्या अधिकारी, सचिवों, जिलाधीशों, आयुक्तों पर अंगुली उठाए, अगर वो धन कमाने, रिश्त, कमीशन के लिए कानूनों की धज्जियां उड़कर जनहितों को नीलाम करने पर तुले हुए हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, सत्ता षडयंत्रों का अड्डा होती है, जहां हर पल, हर कदम, सत्ताधीश, उनके मंत्री, संत्री, अधिकारी, कर्मचारी अपने हितों की खातिरदारी कर जनहित राष्ट्रहितों को दांव पर लगाते रहते हैं। यह सच मानव सभ्यता के प्रार्थुभाव से लेकर अंत तक चलता रहेगा, फिर भारत भूमि जहां कहा जाता है ३२ करोड़ देवी-देवता पैदा हुए, तो इसके पीछे का सच यह भी है कि ३२ करोड़ देवी-देवताओं ३२०० करोड़ दैत्य, दानवों, राक्षसों का संहार किया, या उनसे जनहित की रक्षा की अर्थात् चारों तरफ कल भी मानवों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति थी आज भी है, कल भी रहेगी।

यदि मनमोहन सिंह उनकी अम्मा यूरोपियन एजेंट सोनिया अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के चलते १२० करोड़ लोगों के हितों को दरकिनार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं और विश्व के महादानव बुश के हाथों गिरवी कर दिया है। मात्र कमीशन के लिए।

अब प्रश्न उठता है कि इस राष्ट्र के बुद्धिजीवी और मीडिया क्या कर रहा है, तो आखिर इन्हें भी विज्ञापन मिलते रहे, फिर मीडिया में लोग कितने पढ़े-लिखे, कितनी गहरी सोच और कितना भविष्य में झांककर राष्ट्रहितों को सर्वोपरि मान राष्ट्रहित का ख्याल रखते है। यह मुद्रित और दृश्य प्रसार माध्यमों पर चल रहे तथ्यों से अंदाज लग ही जाता है। किसी को भी राष्ट्रहित से नहीं अपने स्वार्थी को पूरा करने से मतलब है भाड़ में जाए राष्ट्र और आने वाली पीढ़ी।

चीनी इशारे पर...

सामान की बाढ़ भी आने वाली है। शीघ्र ही चीन, नेपाल के माध्यम से सीधे ही अपने जासूसों, आतंकियों की बाढ़ भी 2010 तक भेज देगा। यदि सरकार नहीं चेती तो बिहार, असम, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती उपरोक्त वर्णित कहर भी शीघ्र ही बरपेगा, जिसे भी रोकने की व्यवस्था अभी से करना होगी। इतिहास कम से कम 25 वर्षों का गवाह है कि चीन ने लगातार अपना निम्न स्तर का घटिया माल नेपालके माध्यम से भारत में भेजा, जिसमें घड़ियां, मोबाइल, कम्प्यूटर सामग्री से लेकर हथियार तक भेजे हैं। माओवादियों के आतंकवादियों की फौज खड़ीकर न केवल बिहार वरन झारखंड, मप्र व अन्य राज्यों में भारी आतंक बरपाया है। अब जबकि उनके पाले हुए आतंकियों और नेताओं का कब्जा ही नेपाल पर हो चुका है, तो भविष्य क्या

होगा भारत का, ये शासन में बैठे धूर्त, मक्कार संग्रह की सरकार के साथ ही राष्ट्र के महामानव समझे जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी सोचना होगा, क्योंकि ये गिद्धों की फौज असली शासन 30 से 40 वर्षों तक करती है। इसे नेपाल की हर गतिविधि पर निगाह रखनी होगी। विश्वस्तर पर नेपाल विश्वभर के जासूसों का तस्करो, आतंकवादियों का बड़ा अड्डा है। फिर जब प्रश्न और बात भारत की हो तो नेपाल से भारत में आसानी से बिना वीसा और पासपोर्ट के आने के लिए आसान रहता है। समय माया ने अपने पूर्व के समाचार पत्रों में यह तथ्य भी प्रकट कर दिया था, कि नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार बनेगी, तो परेशानियों का कारवां से भारत को जूझना पड़ेगा। बेहतर है नेपाल के बिना वीसा और पासपोर्ट के

कांग्रेस में मुख्यमंत्री ...

कुछ सामने, कुछ पीछे से, कुछ मंच तैयार होने पर होंगे तैयार

पेज एक से जारी

पैमाना भरने पर छलकता ही है, लात धूंसे तो अपनों पर ही चलाये, चलवाये, खाये और खिलाये जाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश के महामंत्री और जाने क्या-क्या रहे और होंगे या है। वो है सुरेश पचौरी, वो दोनों की बढ़ती या पसरती या पसारी जाती या प्रसारित की जाती लोकप्रियता को बढ़ते देख बेशक तकलीफ में तो है, परन्तु मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री युगों से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हुए थक चुके सुभाष यादव भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, पर बिना शोरगुल किए अपने समीकरणों को जमाने में लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महा घाघ, मक्कार अर्जुन सिंह का पुत्र राहुल सिंह भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार है जो मंच जमाने, जीतने पर प्रकट होगा, वो शांति से कमल, ज्योति, सुभाष, दिग्गी



मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए...

को लड़वाकर मैदान मारने की तैयारी में है। बेशक इस दौड़ में काफी पीछे है। इस दौड़ का सबसे घाघ है दिग्गी दानव, जो दस वर्ष इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है। वह कांग्रेस

की अगर सौ सीटें भी आ गई तो बसपा के बढ़ते प्रभाव से अगर उसकी 10-20 सीटें भी आई तो टुकड़े डालकर उन्हें खरीदकर व अन्य निर्दलियों को मिलाकर मुख्यमंत्री पद

का समय पर दावेदार के रूप में प्रकट होगा। उसका दांव सोनिया को भी भारी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को बुरे वक्त में उसने प्रदेश से हर माह रु. 1000 करोड़ से ज्यादा देकर डूब चुकी कांग्रेस को बचाया है, उसका ये हथियार अंतिम क्षणों में प्रयोग में लाकर वह दावेदारी ठोकेंगा, जो कमल, ज्योति, सुभाष, जमुना, राहुल, सुरेश सबको चारों खाने चित कर देगा। यह सब जब होगा कांग्रेस यदि बहुमत में आ जाएगी तो नहीं आई तो, जो नेपथ्य में हैं वो हाने का टीका सुरेश, कमल और ज्योति पर तो फोड़ ही सकते हैं, फिर भी वर्तमान में वो जहां पर हैं वहां से भी पीछे धकेलने में ये ही हथियार का उपयोग कर उनकी छवि को बर्बाद करने के काम आएगी, जो अगले चुनाव में लोगसभा में काम आएगी।

मनमोहन की नौटंकी...

पेज एक से जारी

कर सकते तो इन हरामखोर भ्रष्टों के कारण जिन्हें अपने कमीशन और धन की वसूली से मतलब है। इतना सारा सच जबकि स्पष्टता के साथ आ चुका है फिर भी ये समझौता तोड़ने को तैयार नहीं है, अभी भी दलीलों का पुलिंदा दिखा रहे हैं राष्ट्र को, आखिर इस शूकर ने पूरी संसद को भ्रम में रखकर जनवरी 08 से अभी तक संसद में क्यों नहीं रखा पूरा मसौदा। स्वाभाविक था सोनिया के इशारे पर पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का अमेरिकी हाथों में गिरवीकर गुलाम बनाने की साजिश रची गई है। ताकि चीन या पाकिस्तान के परमाणु हमले के समय, हमारा राष्ट्र अमेरिकी के सामने गिड़गिड़ाए और वह सुरक्षा देनेके नाम पर अपनी फौजें उतारकर अपने साम्राज्यवाद के पैर भारत में भी जमा ले। सोनिया को राजीव गांधी की जिंदगी में इस राष्ट्र को पुनः गुलाम बनाने के उद्देश्य से ही स्थापित किया गया था, 40 वर्षों की दीर्घावधि के बाद अंततः तक अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रही है। जिस स्व. इंदिरा गांधी ने अमेरिका साम्राज्यवाद के सामने घुटने नहीं टेके। अटल ने अपना रुख नहीं बदला, उसे बिना रक्तपात के ही आसानी से अमेरिका का गुलाम बनो की साजिश रच दी गई।

यह बात पूरा विश्व जानता है कि अमेरिकी संकर कैसे पूरे विश्व में युद्धऔर सहायता के बहाने कैसे 90 देशों पर शासन कर रहा है। जिसके सामने वह ब्रिटेन झुका रहता है, जिसका 100 वर्ष पूर्व कभी सूरज नहीं डूबता था द्वितीय विश्व युद्ध में उसे सहायता के बहाने अमेरिका ने गुलाम बना लिया तो भारत की बिकाऊ मानसिकता की फौज को, तो उसने डालर की कागजी टुकड़ों से ऋणी सहायता के नाम पर वैसे ही कब्जे में कर रखा है अब परमाणु समझौते के बहाने अपनी फौजों को बैठाकर देश में प्रत्यक्ष शासन चाहता है। उसका परमाणु समझौता सीधा अप्रत्यक्ष हथियार वह प्रयोग में ला चुका है।

परमाणु...

सोनिया का कमीशन भी मानें तो रुपए 600 अरब- 600 अरब का कमीशन होगा। इस रुपए 1200 अरब के कमीशन के बदले इस देश की परमाणुवीय सुरक्षा, यूरोपीय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पास गिरवी कर दी गई है। अब इस आई.ए.ई.ए. के विशेषज्ञ भारत के 22 परमाणु ऊर्जा संस्थानों की पूर्ण बारीकी से जांच करेंगे, जिसमें भारत को ये आश्वासन देना होगा कि वह विदेशों से प्राप्त परमाणु ईंधन का उपयोग बिजली उत्पादन के अतिरिक्त किसी में भी नहीं करेगा।

इस प्रकार यदि भारत ने इस यूरेनियम के उपयोग के बाद, परमाणु बमों में उपयोग किया तो तत्काल बाद ही उसकी परमाणु ईंधन आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। कुल सारी कहानी भारी कमीशन की ही थी, जिसके लिए कांग्रेस और संग्रह गिरोह पूरी सरकार के शक्ति परीक्षण के लिए न केवल तैयार हो गया, वरन् सरकार को बचाने के लिए जालसाजी पूर्ण तरीके से सांसदों की खुले में खरीद फरोख्त हुई।

सी.एन.एन. की साइटों के अध्ययन से यह स्पष्ट होत है कि इसमें परमाणु ईंधन आपूर्ति के इस व्यवसाय में अनेकों अमेरिकी व यूरोपियन कंपनियों का भारी फायदा होगा, जिसमें बुश को भी 10% कमीशन भी मिला तो अमेरिकी डालर 15 अरब का प्रत्यक्ष लाभ होगा।

जैसा कि समयमाया ने पूर्व के अपने

अंकों में लिखा था कि सारा खेल मोटे कमीशन को लेकर किया जा रहा है। इस मोटे कमीशन की तैयारी मन मोहन सन 1992 से कर रहा था, जबकि वह राष्ट्र कर वित्तमंत्री हुआ करता था, तब से उसने भारत की परमाणु संस्थानों में आवंटित बजट देना बंद कर दिया था, फिर जानबूझकर जो परमाणु भंडारों पर ऊर्जा का उत्पादन चालू था, ईंधन की आपूर्ति रुकवाकर संकट खड़ा किया, फिर हल्ला मचाया और मचाया, ताकि रुपए 600-600 अरब के कमीशन में हाथ मारा जाए, अब जो परमाणु हम रुपए 100 में तैयार कर सकते थे, वहीं अमेरिकी कंपनियों से रुपए 1000/- में खरीदा जाएगा।

हमारे देश में यूरेनियम प्लूटोनियम, यूरेनियम के अयस्कों के भंडार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक है। उनका प्रसंस्करण तो जानबूझकर नहीं किया जा रहा, वरन उल्टे ही अयस्क लोह अयस्क की तरह विदेशों को मिट्टी के भाव बेचकर उससे प्रसंस्कारित परमाणु ईंधन मोटे कमीशन के लिए खरीदा जाएगा।

वैसे भी कांग्रेस गिरोह के सफेदपोशी अपराधी नेताओं, मंत्रियों, प्रधानमंत्री तक का पुपाना इतिहास गवाह है कि इन्होंने कभी राष्ट्र हिन्दु नहीं वरन राष्ट्र की सत्ता की आड़ में अपने बैंक बैलेंसों की ज्यादा चिंता रही है। अब इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो ही जाता है कि आखिर सरकार को दांव पर लगाकर क्यों परमाणु समझौते का राग अलापा गया।

रूस को घेरने...

पेज एक से जारी

मिसाइलों की सच्चाई अगरस्ट ०८ के मध्य में पूरी दुनिया को अपनी भ्रष्टाचार की साइटों के माध्यम से बता दी थी। तीसरे दिन से ही रूसी प्रधानमंत्री पुतिन ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अमेरिका सहायता के तीन जहाजों के नाम पर जार्जिया को गोला बारूद कमांडो और जासूस भर कर भेजे थे, यह घटना ने इतना तूल पकड़ा कि अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने जार्जिया को धन, बल का लालच देकर रूस के विरुद्ध उकसा कर युद्ध पर आमदा कर एक सात कई खेल खेले, जिसमें सबसे पहला जार्जिया का सच्चा हितेपी बनकर दिखाने, उसे अपनों से अलग करने, दूसरा रूस की मारक क्षमता का प्रदर्शन

देखने, तीसरा भविष्य में चूंकि रूस और जार्जिया में चूंकि आमने-सामने की मुठभेड़ हो चुकी है, अब कभी जार्जिया रूस के पाले में बैठने लायक नहीं रहा, चौथा अब इस तरीके से अमेरिका ने रूस के सीमा से सटे रूस के ही राज्य को अपना मित्र बनाकर अपनी फौजों और अपने नाटो गुलामों की फौजों से सीधा रूस की सीमा पर युद्ध करने का अड्डा तैयार कर लिया। बेशक इसके जवाब में बुलगारिया से रूस ने अमेरिकी राजदूत को भगवाकर बुलगारिया में पहली बार अपने आधुनिक युद्धक विमान को बुलगारिया की धरती पर उतारकर अमेरिकी गुंडे को बराबरी की टक्कर देने को इरादा साफ कर दिया है।

भारत में आवाजाही बंद कर दी जाना चाहिए, अन्यथा दुष्परिणामों को जिसमें आतंकियों, अवैध हथियार से उत्पन्न परिस्थितियों का झेलना पड़ेगा। पुराना आतंकियों के आने-जाने के मामले में नेपाल का किस प्रकार उपयोग किया गया है कई बार सामने आ चुका है। अभी भी वक्त है इस शुरुआत में ही इसकी समीक्षा की जाना चाहिए, वरना अभी तो बाढ़ का तांडव हुआ है। फिर पूरे बिहार में चाड़ना निर्मित हथियारों का भी तांडव होगा। अब चीन हर प्रकार के कार्यों को अंजाम देगा, जिसमें नकली नोटों से लेकर, सभी प्रकार के राष्ट्र विरोधी कार्यों की बाढ़ भी आएगी। बिहार के मधेपुरा, सहरसा, अररिया, सुपौल और पूर्णिया के डेढ़ से दो हजार गांवों में नेपाल के पानी छोड़ने से 40 लाख से ज्यादा आबादी

प्रभावित हुई, परन्तु भारत सरकार के गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के राजदूत को बुलाकर पूछताछ व निर्देश तक नहीं दे सकी। भारत सरकार स्वयं आक्रांत है चीन के भय से, इस बात से सरकार के निक्मपेन का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह बात भारत की जनता अच्छी तरह से जान ही चुकी है कि ऐसी सारी आपदाएं बाढ़, भूकंप, आतंकवादी हमले आदि सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों की कमाई का व लूटपाट का साधन बन चुके हैं। इन्हें तो ऐसी आपदाओं का कमाई के लिए इंतजार रहता है। भले ही बिहार की बाढ़ में 2 से 3 लाख मरे हो, इन्हें मुआवजा बांटने, आपदा निधि में, पुनः निर्माण करने में करोड़ों रुपए की कमाई का साधन मिल गया तो कोई क्यों कर बात करेगा?

रूस को घेरने...
मिसाइलों की सच्चाई अगरस्ट ०८ के मध्य में पूरी दुनिया को अपनी भ्रष्टाचार की साइटों के माध्यम से बता दी थी। तीसरे दिन से ही रूसी प्रधानमंत्री पुतिन ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अमेरिका सहायता के तीन जहाजों के नाम पर जार्जिया को गोला बारूद कमांडो और जासूस भर कर भेजे थे, यह घटना ने इतना तूल पकड़ा कि अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने जार्जिया को धन, बल का लालच देकर रूस के विरुद्ध उकसा कर युद्ध पर आमदा कर एक सात कई खेल खेले, जिसमें सबसे पहला जार्जिया का सच्चा हितेपी बनकर दिखाने, उसे अपनों से अलग करने, दूसरा रूस की मारक क्षमता का प्रदर्शन

भ्रष्ट पूर्व सं. 2 का. अं., अ.यं. बन पुनः इंदौर में

धूर्त के.सी. जैन उर्फ नेता कैलाश वैद

बाप लोनिवि में अभियंता, बेटा ठेकेदार

इंदौर। म.प्र. लो.नि.वि. में वर्तमान में अधीक्षण यंत्री के पद पर विराजे कैलाश वैद उर्फ के.सी. जैन, महाजालसाज और भ्रष्ट होने के साथ ही इसका बेटा ठेकेदार मनीष जैन भी इसके पद चिन्हों पर ही चलता है, बाप ने अरबों रुपए का चंदन अपने कार्यपालन यंत्री पद पर रहते हुए खंडवा, इंदौर संभाग क्रमांक 2 में लगाया। बेटे को अपना प्रभाव दिखाते हुए अनेकों ठेके दिलवाए। आधे अधूरे स्तरहीन काम करने के बाद भी उसके धड़ल्ले से भुगतान करवाये जाते रहे, अभी के ताजा मामलों में भी इसे अब पदोन्नत करके उच्च पदस्थ किया गया तो भी इसने न तो मकान छोड़ा और न ही किराया दिया, अब विभाग से कह रहा है किराया माफ कर दो या विभागीय दरों पर ही किराया लो। इसके आवास पर लगे फोन बिलों में भी पात्रता के विपरीत इसने फोन के बिलों का भुगतान सीमा के विपरीत हजारों का भुगतान विभाग से ही करवाया।

सांवेर जेल के मामले में ही पुराने ठेकेदार से कार्य छीन कर अपरने बेटे की साझेदारी में कार्य किया और जेल का वह कार्य भी अधूरा छोड़ दिया। हाल ही में उच्च न्यायालय के भवन निर्माण का ठेका भवन व पथ निर्माण हेतु अपने भाई को दिलवाया, उसमें भी पथ का क्रांकीट निर्माण का भुगतान भी भवन निर्माण की दरों से वसूल लिया गया, जबकि वह भवन निर्माण से 35% कम दरों पर निर्माण होता है। उसको भी अभी विभागीय वसूली बाकी है।

इस हरामखोर ने कदम-कदम पर करोड़ों की जालसाजियों को अंजाम दिया और कमाए गए भ्रष्टाचार के धन को भाई और बेटे की ठेकेदारी में लगाया गया। हाल ही में इस भ्रष्ट से जब चर्चा की गई तो पुराने पापों के दस्तावेजों के संबंध में भारी बिफरा।

जैन समाज में यह अपवाद समाज के हित या उसके विकास के लिए नहीं वरन्, यह धूर्त वहां भी नेतागिरी के मंच से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बैठा है। वैसे तो यह अधीक्षण यंत्री के शासकीय पद पर रहते हुए अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता है, परंतु नेतागिरी में यह कैलाश वैद के नाम से अपनी नेतागिरी की दुकानदारी से समाज के मंदिरों में एकत्रित धन और सम्पदा पर इसकी निगाहें गड़ी हैं। अब इस मंच से उस धन को अंटी करने की जुगाड़ में है। इसकी जालसाजियों का अंदाजा शासकीय कार्यों में कैलाशचंद जैन और समाज के नेतागिरी में कैलाश वैद की दुकानदारी के डबल रोल से ही लग जाता है।

लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जासंगे छूट

पूरे देश में शिक्षा माफियाओं का जाल अधिकांश निजी व शास. शिक्षण संस्थानें जालसाजों के अड़े

रुपए 5 लाख करोड़ से ज्यादा की दुकानदारी है, शिक्षा का व्यवसाय

पूरे देश में पिछले 30 वर्षों से शिक्षापूर्णातः एक सबसे सफल व्यवसाय के रूप में परिणित होकर जालसाजों, भ्रष्टों और अव्यशाओं का पंसदीदा शौक बन चुकी है। अब इस व्यवसाय में शिक्षाविद्, उच्च ज्ञानी-ध्यानी न होकर विशुद्ध गुण्डें, बादमाशों, अपराधियों, भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं जालसाजों की फौज ने इस पर कब्जा जमा रखा है जो जितनी बड़ी संस्थाएं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय जितने बड़े हैं वहां उतने बड़े भेडिये, सफेदपोश, नकाब ओढ़कर शिक्षाविद् बने बैठे मिलेंगे। जिनका विशुद्ध व्यवसाय धन नौचाना, महिला शिक्षाकर्मियों, छात्राओं रूपी नवयौवनाओं को भोगने से लेकर उनकी नग्न सीडियां बनाकर उन्हें और उनके माता-पिताओं को ब्लैकमेल करने का धंधा करने में भी पीछे नहीं हैं। इंदौर प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां की ऐसी सीडियों तक भी सार्वजनिक हो चुकी है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आत्माएं भी जब शिक्षा के व्यवसायिकरण से चीख उठी हो तब इस पवित्र पैसे में छायां और आई गंदगी, नॉचखसोट का अंदाज प्रबुद्ध पाठक लगा सकते हैं।

इंदौर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में ही नहीं वरन् राष्ट्र में भी एक जानामाना नाम बन चुका है। इसके विपरीत कुंजडों की सब्जी-भाजी की दुकानों की तरह फुटपाथ से लेकर रिलायंस फ्रेश के भंडारों की तरह ही इस पवित्र शिक्षा जैसे पैसे की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है।

आए दिन कभी आशाराम बापू के स्कूलों में बच्चों की लाशें मिल रही हैं तो विश्वविद्यालयों से लेकर पूरे देश के छोटे विद्यालयों तक में



यौनाचार कांडों की बाढ़ सी आई हुई है। जब तक शिक्षा सरकारी हाथों में थी तो फिर भी स्थिति इतनी बदतर नहीं हुई थी। जब से शिक्षा का निजीकरण होकर व्यवसायीकरण शुरू होकर बाजारीकरण शुरू हुआ, शिक्षा के नाम पर कागजी टुकड़ों को बेचने की आड़ में लूटपाट और यौनाचार का अड्डा बनकर रह गई है।

ऊपर से इंदौर के ही भास्कर, नई दुनिया जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में रोजमर्रा के छपने वाले समाचारों ने जिसमें इस स्कूल में फैशन हुआ, इस स्कूल में मौजमस्ती की ये कक्षाएं लगी, वहां की शिक्षिकाओं और शिक्षकों ने भी नाचगानों की महफिलों में भाग लिया, ये सिद्ध करने के

लिए पर्याप्त ठोस आधार प्रदान कर दिया।

अधिकांश निजी विद्यालय, महाविद्यालय, उन्हीं गुंडों बदमाशों, सफेदपोश माफियाओं, नेताओं, भ्रष्टों, डॉक्टरों, अधिकारियों, पुलिसियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिन्होंने दो नम्बर का काला धन अत्याधिक इकट्ठा कर लिया है, यदि आयकर विभाग धड़ल्ले से कुंजडों की दुकानों की तरह खोले जा रहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, कम्प्यूटर, साईंस, होम्योपैथिक के साथ ही हर तरह के धन के स्रोतों की जांच करें तो बड़े भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों, शासन में बैठे सचिवों से लेकर डॉक्टरों, छोटे-छोटे पुलिस निरीक्षकों, उप निरीक्षकों के धन का विनियोजन ही पाएगा। जिसमें ऐसे हरामखोर भ्रष्टों द्वारा धन एकत्र किया जाकर लगाया गया है।

वर्तमान में सारी शिक्षण संस्थाएं जिनमें कोचिंग संस्थान भी शामिल है अरबों रुपए की लूटपाट की सम्पत्तियों जो वैध-अवैध रूप से एकत्रित की गई है, जिसमें आयकर, केंद्रीय कस्टम, एक्साइज व सेवाकर के अधिकारी और कर्मचारियों की भी मिलीभगत होने के साथ संरक्षण भी है। खुलकर वसूली जाने वाली शिक्षण शुल्कों में शून्य उड़ाकर सेवाकर और आयकर में भी करोड़ों रुपए की चपत लगाते हैं।

इन सबके चलते विद्यार्थियों के माता-पिता शासन और न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च

न्यायालय की शरण लेते भी हैं तो उनसे कोई उन्हें बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल जाता, क्योंकि ये जालसाजों की लॉबी धन और बल का उपयोग कर अधिकांश फैसलों में उलझन भरे शब्दों और वाक्यों का उपयोग कर न्यायालय भी अंत में इनको लाभान्वित करते हुए फैसले ही दे देते हैं। जिससे विद्यार्थियों को मनचाहा लाभ तो नहीं मिल पाता, इन श्वानों के वर्चस्व के सामने और आर्थिक बोझ को वहन करना ही पड़ता है।

अधिकांश निजी स्कूलों और महाविद्यालयों में अपेक्षित शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं जैसी आधारभूत संरचनाओं का ही अभाव हो, म.प्र. व अन्य राज्यों के उच्च शिक्षा विभाग, वहां के विश्वविद्यालयों के अधिकारी खुलकर धन लेकर मान्यताएं बांट रहे हैं। न केवल मान्यताएं बांट रहे हैं, वरन् काउंसिलिंग के नाम पर विद्यार्थियों को जबरन ऐसे कालेजों में धकेला जा रहा है जहां विद्यार्थियों के माता-पिताओं का धन, बैंक ऋण तो व्यर्थ ही जा रही है हो सकता उनके जीवन का कीमती समय व्यर्थ किया जा रहा हो, ऐसे संस्थाओं के सफेदपोश माफियाओं को कौन सजा देगा?

जहां तक मीडिया का सवाल है तो अब तो बड़े-बड़े संस्थानों, अगर इंदौर को ही लें तो यहां तो भास्कर, नई दुनिया के संचालक ऐसे जालसाजों के साथ मिलकर बाकायदा शिविर आयोजित कर न केवल विद्यार्थियों का भविष्य चौपट करते हैं, वरन् उन जालसाजों को धन लेकर उनकी जालसाजियों को ठोस मंच देकर उन्हें संरक्षण भी दे रहे हैं। फिर मीडिया के शूकरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल भविष्य क्या होगा, जब ऐसे आधी-अधूरी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा और क्या करेंगे भविष्य में।

इस क्षेत्र में इंदौर ही क्या हिन्दुस्तान टाइम्स, टाईम्स ऑफ इंडिया आज तक जी, स्टार, न्यूज चैनल भी ऐसे कार्यों को अंजाम देने में पीछे नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। कानून है, विज्ञापनों की आचार संहिता (मेडिकल कोड एंड इथिक्स ऑफ एडवरटाइजमेंट एक्ट 1956) है पर उसमें भ्रामक विज्ञापन देने और छापने वालों के विरुद्ध कोई कड़ी सजा का प्रावधान न होने और इस अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार न होने से कोई भी व्यक्ति मीडिया और विज्ञापनदाता के विरुद्ध न्यायालय में खड़ा नहीं हो पाता।

लो.नि.वि. रिटायर होते मु. अभियंताओं ने धन खर्च कर बे रहे

भ्रष्टों को धन के बदले सेवा विस्तार

30-35 वर्ष लूटकर दिल नहीं भरा, दो वर्ष लूट के बादले बंटधार

भोपाल। म.प्र. लोक निर्माण विभाग में सेवा निवृत्त हो रहे 5 मुख्य अभियंताओं और 11 सेवा निवृत्तों को रुपए 1 करोड़ प्रतिवर्ष के बदले 5 वर्ष का सेवा विस्तार देने के लिए प्रमुख अभियंताओं कार्यालय, सचिवालय से मुख्य सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक तेजी से फाइलें दौड़ रही हैं।

इस लाइन में इंदौर का मुख्य अभियंता पी.सी. अग्रवाल स्वयं अपनी फाइल लेकर बाबुओं को पैसे बांटता हुआ पिछले 15 दिन से भोपाल-इंदौर दौड़ रहा है। इस धूर्त के बारे में बता दें कि वैसे तो ये महाभ्रष्ट, मक्कार बड़ा ईमानदार होने का पाखंड करता है। इंदौर-उज्जैन मार्ग में हुए भ्रष्टाचार की कहानी और फाइलें लोकायुक्त में चल रही हैं। इस धूर्त के बारे में विभाग में चर्चा है कि ये रिश्तत के धन का लेनदेन कार्यालय में ज्यादा नहीं करता। इसके खास चेलों में म.प्र. लोक निर्माण विभाग सं. क्र.2 का कार्यपालन अभियंता

ए.पी. राणे एक का का.अ. रा. का सांवला, धार का गुप्ता, अत्यंत प्रिय हैं। जिनसे सीधे धन नहीं ले रहा है, उनसे व्यक्तिगत कार के पेट्रोल बिलों, टेलीफोन बिलों व अन्य खरीदी का भुगतान करवाने के लिए बिल थमा देता है। अपनी सरकारी गाड़ी, बीवी उपयोग में लेती है और ये अपने लिए का. अभियंताओं की गाड़ी उपयोग करता है।

इंदौर-उज्जैन मार्ग पर हाल ही में अप्रैल मई में 9 किमी से 37 किमी तक रुपए 4 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए थे, जबकि 1 से 8 कि.मी. इंदौर सं.क्र. 2 के पास ही था, क्योंकि इस मार्ग पर 6 से 8 किमी में 8वां किमी सबसे ज्यादा खस्ता हाल रहता है। अभी भी जबकि पिछले जून-जुलाई-अगस्त में मात्र रह-रकर 20'' इंच भी ढंग से नहीं गिरा है। एम.आर.10 से बीएसएफ की फायरिंग रेंज तक का मार्ग गंभीर हालत में है। 9 किमी से 37 किमी

तक रुपए 4 करोड़ परफार्मेंस गारंटी के अंतर्गत खर्च किए गए थे। सड़कों पर जहां-जहां गड्ढे हुए अधिकांश स्थानों पर मिट्टी भर दी गई है। फिर 26 कि. 28वें किमी तक को काम नहीं हुआ, फिर भी बिलों का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

29 कि.मी. में काम मात्रा थोड़ा ढंग से 15-17 किमी में हुआ। 10-12 कि.मी. में दोनों तरफ की पट्टियां नहीं भरी गईं। जबकि जून के अंत तक इस हरामखोर पी.सी. अग्रवाल ने अपने मित्र ठेकेदारों को छोटे-छोटे ठेके दिलवा कर काम करवाया और अधिकांश भुगतान में अपना कमीशन सेटकर अपने कमेरे में बुलाकर ठेकेदारों का भुगतान करवाया गया, जबकि ठेका एक ही ठेकेदार का दिया गया था। इनकी ईमानदारी करने के ढोंग की सत्यता समय माया प्रमुखता से छापता रहा है। फिर यदि से श्वान ईमानदार होने का जो ढोंग कर रहा है तो चुपचाप ईमानदारी से 30-

09-08 को सेवा निवृत्ति ले 60 वर्ष का हो चुका है जो करोड़ों इकट्ठा किए हैं बेटे को विदेश भेजा है, उस धन को ही मजे ले। पीछे वालों का हरामखोर क्यों हक छीनने पर तुला है। फिर रुपए 1 करोड़ का भुगतान भी तो भ्रष्टाचार के कमाई से ही करेगा, सेवा विस्तार मिलते ही फिर लूटपाट कर बांटाधार करेगा, पर हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर। सितम्बर 08 इस विधानसभा का आखरी माह है, मंत्री, मुख्यमंत्री भी मुखरों की तरह जिससे जो मिले बांटोरो कल सत्ता रही न रही के कारण जान बूझकर इस भ्रष्ट के साथ 4 और सेवानिवृत्ति पा रहे मुख्य अभियंताओं को सेवा विस्तार दे ही रहे हैं।

साथ ही 11 सेवानिवृत्त हो चुकों से भी धन लेकर विस्तार देने की तैयारी में है। हर कोई भागते भूत की लंगोटी छुड़ाने और बटोरने में लगा है।

क्या आप अपने बच्चों को खेल-खेल में पढ़ते-पढ़ते देखना चाहते हैं, तो बिलियंट किड्स है आ...

WANTED
English Teacher
for Class
9th to 12th

बिलियंट हा. से. स्कूल
578, छातीवाल टैंक, इन्दौर • फोन : 4092864

कॉमर्स, मेस, साईंस, बायो
नर्सरी से कक्षा 12वीं तक
प्रवेश प्रारंभ - टाई वर्ष से अधिक उम्र

आ.विकास के रूप 4324 करोड़ का दुरुपयोग मुख्यमंत्री की घोषणाओं व दुहाई पर पत्नीता अधिकारियों ने हड़पें अरबों, घोषणाएं व दुहाई मिथ्या

म.प्र. में भाजपा का मु.मं. शिवराज सिंग की आदिवासी विकास की कितनी भी घोषणाएं करें और दुहाई दें परंतु वल्लभ भवन से लेकर जिलों और विकास खंडों में बैठे अधिकारियों द्वारा आदिवासी विकास और कल्याणमद में जारी किए गए रूप 43.24 अरब के उपयोग को अंकेक्षण, महालेखाकार ने स्वयं ही संदिग्ध माना है, भ्रष्ट अंकेक्षकों ने भी माना कि रूप 70.30 करोड़ अवैध रूप से निजी खातों में जमा पाएगा।

म.प्र. के धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी जो इंदौर संभाग के आदिवासी जिले हैं, मोटे अनुमान के अनुसार हर वर्ष रूप 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला होता है, जिसे इंदौर संभाग का संभागायुक्त स्वयं हरामखोर बंदरबांट कर अधिकांश मामलों को दबा देता है।

जबकि म.प्र. में छिंदवाड़ा, अनूपपुरा, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट, सिधी, सतना, बैतूल में भी हर वर्ष आदिवासी विकास के नाम पर मिलने वाली छात्रवृत्तियों, पुस्तकों, छात्रावासों में खेल सामग्री, भोजन वस्त्र, छात्रावासों, ग्राम पंचायतों, नाम पर भी रूप 2000 से 3000 करोड़ का घोटाला सन् 2000 से किया जा रहा है। चूंकि केंद्र से लेकर राज्यों को सचिवों से लेकर जिला विकास खंडों तक में सबसे ज्यादा स्कूली शिक्षा पर खर्च किए जा रहे धन में भारी लूटपाट का तांडव चल रहा है। अधिकांश पदों पर भ्रष्टों का बोलबाला है। इन आदिवासी जिलों में अधिकांश अधिकारियों पर अनेकों भ्रष्टाचार के मामलों लंबित होने के बाद भी एक ही स्थान पर इन अधिकारियों को वर्षों गुजर जाते हैं। धार का ही सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला पर न केवल भ्रष्टाचार के अनेकों मामले लंबित हैं इसके विपरीत इस साधारण से सांख्यिकी अधिकारी को धार में ही पुनः सहायक आयुक्त पद पर बैठा रखा है। जबकि इस श्वान के विरुद्ध खरगोन में भ्रष्टाचार में निलंबन किया गया था। इसके अधिकांश मामलों में छात्रावासों के लिए नियम विरुद्ध खरीदी छात्रावासों के निर्माण, छात्रावासों, आदिवासी विकासखंडों में कर्मचारियों, शिक्षकों की नियुक्ति में ही इसने करोड़ों रूपए कमाए हैं।

इसी प्रकार झाबुआ में बैठे बी.जी. मेहता को 4-5 वर्ष के बाद धार से स्थानांतरित करवाया गया था तो झाबुआ में इस श्वान ने लूटो और लुटाओ के अंतर्गत चारों तरफ से लूटपाट करने के लिए उसे वहां स्थापित दे दिया गया है। वहां भी 4 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं। इसका भी छात्रावासों की खेल, वस्त्र, पुस्तकें, निर्माण, भोजन आदि के क्रय में लंबे-चौड़े घोटाले किए हैं। इन सबकी अधिकांश जांचों को इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय और संबंधित जिलों के जिलाधीशों को टुकड़ा मिलने से दबा दिया जाता है।

सभी आदिवासी जिलों के जिलाधीश भी दोनों हाथों से लूटने के लिए ऐसे सभी विकास कार्यों, शिक्षा छात्रवृत्ति, छात्रावासों की खरीद में अपने मातहतों को सब नियम कानूनों को ताक में रखकर अरबों की खरीदी, वितरण में पूरी छूट देते हैं। वैसे तो अधिकांश आदिवासी जिलों में शासकीय धन डकारने वाले शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों का पूरा माफिया गिरोह सक्रिय होता है जो हर नई योजना, कार्य के धन पर निगाह रखता है। धन आते ही कहां से झूठे व्हाउचर लाते हैं कौन सा ट्रांसपोर्टर आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, कितने कमीशन पर झूठे बिल देगा, वैसे तो वहां के क्षेत्रीय कर्मियों और अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम से अरबों रूपए के फर्जी बिलों का भुगतान होता है, चला आ रहा है।

इस संदर्भ में धार का ही उदाहरण लें, धार जिला पंचायत में आर.के. गुप्ता को म.प्र. जल संसाधन का एक एस.डी.ओ., सहायक अधिकारी के रूप में बैठा है ये हरामखोर इतना घाघ है कि कोई भी केंद्रीय या राज्य की योजना कैसी भी किसी भी विभाग की हो उसमें अगर मोटा धन करोड़ों में आया है तो इस योजना को बारीकी से समझना, उसकी कानूनी औपचारिकताएं कैसी पूरी होंगी, धन कैसे डकारना है, किसको कितना बांटने से काम चल जाएगा, पकड़े जाने पर किसे कहां फंसा कर निपटाना है, ये आर के गुप्ता उसका षड्यंत्र रचकर पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बातों में लेकर इस योजना को झटकना, फिर जिलाधीश को समझाने के लिए मु.का. अधिकारी के ज्ञान से लेकर जिलाधीश से आवंटन बदलवा कर कब्जे में लेना, फिर उस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को विश्वास में लेकर जालसाजी पूर्ण तरीके से स्वयं शेरू हिस्सा डकार कर छान्छ पोंछने के लिए छोड़ देना।

इस कार्य में सूत्रों के अनुसार गुप्ता अपनी कमिसन बीवी का भी उपयोग करता है। खबरें तो यहां तक भी हैं, अगर कोई मोटी योजना हाथ में नहीं आ रही है या हाथ से जा रही है। तो बीवी अपने खूबसूरत अंदाज, आदाओं से मु.का.अ. जिलाधीश या जो भी प्रभावशाली होता है, अपने अंदाज में अपनी तीरंदाजी कर सामने वाले अधिकारी से बात मनवाकर अपने पति का रास्ता साफ करती है। जितनी भी पार्टियां धार के कलेक्टर आफिस में अधिकारियों से संबंधित होती हैं, उनकी वीडियो शूटिंग में इनकी सुंदरता और एक्टिंग के जलवे देखे जा सकते हैं। ऐसी अधिकांश योजनाओं को ये श्वान नॉचकर कागजी खानापूर्ति कर योजना का बेहतर क्रियान्वयन दिखाकर धन हड़प कर गुप्ता फिर इन योजनाओं के झूठन चाटने के लिए संबंधित अधिकारी को देकर अगले शिकार पर निकल पड़ता है।

छोटे शहरों के विकास पर भी ध्यान दिया जाए महानगरों में सुविधाओं का अभाव, संस्थानों का दबाव

इंदौर। दिनोंदिन बढ़ती आबादी, सिकुड़ता यातायात, सिकुड़ता मानव जीवन, महंगी सुविधाएं, महंगा जीवन इस पर भी नए संस्थाओं का बोझ बढ़ाना कितना और कहां तक उचित होगा? ये भूत और वर्तमान से भविष्य की कल्पना की जा सकती है। जब इंदौर में पुराने व नए रहवासी क्षेत्रों में ही टैंकों से वर्षों से पानी बांटा जा रहा है। यातायात के बढ़ते दबाव से सड़कें सिकुड़ रही हैं, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा हो गया हो इंदौर में जीवन तो फिर बड़े-बड़े उद्योगों, संस्थानों को लादने से भविष्य क्या होगा।

बेशक विकास होना चाहिए, परंतु जहां बिलकुल भी विकास न हुआ हो जिन्हें वर्तमान में भी आदिवासी जिलों के नाम से पुकारा जा रहा हो, क्या विकास वहां नहीं होना चाहिए, उन्हें विकास की आवश्यकता नहीं है? ऐसे विशाल संस्थाओं, जिसमें भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान भी है, आजूबाजू के धार, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, देवास, शाजापुर जैसे छोटे जिलों में खोलकर न केवल छोटे शहरों की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाई जा सकती है।

वर्तमान में अकेले इंदौर में ही तीन अलौपैथिक मेडिकल कालेज 5 से ज्यादा डेंटल कालेज, 30 से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेज, 10 से ज्यादा फार्मसी कालेज, 5 के लगभग होम्योपैथिक कालेज, प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान के साथ प्रबंधन, कम्प्यूटर, साइंस व अन्य कालेजों की बाढ़ आ चुकी है। स्वाभाविक है इन संस्थानों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों का दबाव अप्रत्यक्ष रूप से शहर में बढ़ा दी है। जो यहां के इंदौर के स्थाई निवासियों की श्रेणी में भले ही न हो, परंतु रहने, खाने, पीने, सड़कों का उपयोग, जल, विद्युत का उपयोग से यहां के रहवासियों को तो उनका अप्रत्यक्ष पलासिया चौराहे, भंवरकुआं पर जब ऐसे कोचिंग, शिक्षण संस्थान, विद्यार्थियों की छुड़ी करते हैं तो ये छोटे शहरों और कस्बों से ओ वाल बुंदेलखंड व अन्य क्षेत्रों के प्रदेश व देश के विद्यार्थी जंगली जानवरों से ज्यादा बदतर तरीके से यातायात प्रभावित करते हैं। शाम 5 से 7 बजे तक हालात पूरे इस महानगर में गंभीर हो जाता है, जबकि सड़कें अभी भी उतनी ही हैं। ठीक है धीरे-धीरे विकास हो रहा है।

बड़े शहरों में आबादी बढ़ने से अपराधों में भी बेइंतहा वृद्धि हो रही है। पिछले 1 वर्ष में ही 4-5 बैंक डकैतियां पड़ चुकी हैं। अथवा साधन पुराने स्तर पर ही आबादी तिगुनी, फिर भी नए बड़े उद्योगों, कार्पोरेट कार्यालयों, बढ़ते शिक्षण संस्थानों के विकास के साथ हर वस्तु जिसमें जमीनों, श्रमिकों से लेकर हर वस्तु की कीमतें भी बढ़ती है। ये विकास के दोष भी हैं। आखिर ऐसा विकास केवल बड़े शहरों में ही क्यों हो? छोटे शहरों में भी ऐसे शिक्षण संस्थान खोले जाए, ताकि वन पर बसी हुई आबादी भी अपना मानसिक व आर्थिक विकास कर सके, वहां की युवा पीढ़ी को ऐसे संस्थानों को देखकर पढ़ने और बढ़ने की ललक जागे और वे भी अपना, अपने परिवार व समाज का सम्पूर्ण विकास कर सकें। इससे न केवल विद्यार्थियों, श्रमिकों व पलायन रुक सकेगा, वरन् धार, झाबुआ जैसे आदिवासियों और जिलों में अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

झाबुआ में बड़े औद्योगिक शिक्षण संस्थान, उद्योगों के स्थापित होने से वहां के स्थानीय लोगों को काम मिलेगा तो स्वाभाविक है हत्याये लूटपाट में कमी आएगी। बेशक सफेदपोश, नेताओं अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश और देखरेख बढ़ेगी तो तकलीफ होगी।

महंगी जमीनों,
महंगा जीवन,
बढ़ते अपराध,
दमघोटू
वातावरण

उड़ीसा में ईसाई मिशनरियों के षडयंत्र के विरुद्ध आभ

पोप की बपौती नहीं भारत

शताब्दियों से चल रहे खेल का निकलने लगा तेल



ने अपने गुलाम होने का परिचय दिया।

यूरोपियन एजेंट सोनिया इस देश में राजीव गांधी से... में ब्लैकमेल कर शादी इसलिए ही करवाई गई ताकि वो आने वाले कल में इस राष्ट्र पर राज करे, इस देश में शीर्ष पर बैठे नेहरू खानदान में इस महिला को स्थापित करने का उद्देश्य सही था कि इटली में बैठे ईसाई धर्मगुरु पोप का सीधा प्रतिनिधि देश में ईसाई धर्म प्रचार-प्रसार और संरक्षण नियंत्रित करें। पिछले ४० वर्षों से सोनिया सत्ता में बैठकर भारत में यही कर भी रही है।

यही कारण है कि इटली में बैठा पोप सोनिया के दम पर भारत को अपनी बपौती मानकर धमकाता है, उसके धमकाने पर भारत में बैठी ईसाई शिक्षण संस्थाओं ने १ दिन के लिए पूरे भारत में सारी ईसाईयों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को

बंदकर दिया था, इससे आने वाले भविष्य के लिए यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कल अगर इस धूर्त पोप की बात नहीं मानी तो आज इसने शिक्षण संस्थाएं बंद करवाई हैं, आने वाले कल में ये आगे बढ़कर देश बंद करना तो साधारण सी बात है। ये भी मुस्लिम आतंकवादियों की तरह हिंदुओं के मंदिरों और ठिकानों पर बम धमाके भी करेंगे।

यदि उड़ीसा में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए मंदिर के पुजारी की हत्या के बदले जनाक्रोश फूटा और आगजनी हुई, तो कितने वर्षों से गरीब आदिवासी, हरिजनों व अन्य जाति के लोगों को धन का लालच देकर खुलेआम ईसाई ननों के साथ यौनाचार कर, ब्रदर-ब्रदर कर घर में घुसने हिंदु पुरुषों से यौनाचार कर उन्हें डरा-धमकाकर बलात्कार की सजा दिलवाने का भय दिखाकर ईसाई धर्म मानने के लिए विवश किया जा रहा होगा, स्वाभाविक जनाक्रोश फूटा, हिंसा और आगजनी में बदल गया जो अभी तक चल रही है।

सोनिया उसकी गुलाम कांग्रेस गिरोह एक पादरी के धिनौने गैर कानूनी कृत्यों से परेशान अगर दारा ने उसकी हत्या कर दी तो उसे शीघ्र



ही फांसी की सजा सुना दी गई, अब जब हिंदु पुजारी हनुमंथौया की हत्या हो गई तो वह श्वान इटली से भारत को अपनी बपौती समझ गुरा रहा है। स्वाभाविक है अपनी चेली के वर्चस्व के दम पर ही उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वहां बैठकर भी गुरा सके। ईसाईयों ने धर्म परिवर्तन तो किया साथ ही अपनी ईसाई ननों और महिलाओं से अन्य जाति के पुरुषों के संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य कर उनके मुंह पर ताला मारकर उन छोटी जाति की हिंदु, आदिवासी महिलाओं से ईसाई पुरुषों ने न केवल बच्चे पैदा किए वरन मूल भारतीय

शेष पेज ७ पर

Admission open FOR CLASSES

PINK FLOWER H.S. SCHOOL
Stadium ground Nanda Nagar, Indore Phone: 2435124

• Nursery to 12th
• Hindi, Sanskrit
• Computers & Drawing
• Nursery to 12th
• English Medium

Requires
Lecturer in English, Sanskrit, Physics, Chemistry & Maths.
For Primary Section in Hindi to Fluency in Spoken English is essential for Primary Section.

Preference will be given to candidates having 2 years exp. of teaching in school level. Salary as per school rules. Computer & Drawing Education from 11th Teaching of Visual Culture & More items.

नवरात्रि एवं दशहरे की शुभकामनाएं
अम्बिका साल्वेक्स

★ लिमिटेड ★

रजिस्टर्ड ऑफिस :- 304 सत्पत्नीता
★ अपार्टमेंट ★
90/40 स्नेह नगर मेनरोड, इंदौर (म.प्र.)
★ 452001 झेंडिया ★
★ फोन :- 91-0731-2471655 ★

दस्तावेज़ न्यूइंडोरेयत, न्यू-नैबव रोड नम्बर-457226 (जल्लय)
फ. इ. फोन :- 91-7414-500923, 500922 ई. नम्बर 91-741 4-5001 57

हेड ऑफिस :- डी.पी.ए.सी., पुरासायावमंडी, बरकपुर बंदर (फ. इ.)
झेंडिया फोन :- 91-7422-45576, 52990 ई. नम्बर :- 91-7422-52990

केंद्र व राज्य की भ्रष्ट आई.ए.एस. लाँबी लगी है लगातार संशोधन में सूचना अधिकार अधि. 05 का बलात्कार

भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर सूचना आयोग तक कर रहे जालसाजियां

विश्व में भ्रष्टाचार के मामले में कभी 5वां, कभी 17वां कभी 70वां क्रम देकर भारत के शासन प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार के किस्से, चर्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होते रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में भारत के सभी केंद्र व राज्यों के शासन-प्रशासन ने अपने भ्रष्टाचार, लूटखसोट के अपने मानदंड स्थापित कर पूरे विश्व में जो ख्याति अर्जित की है। इस देश की गरीबी, लाचारी, परेशानी से पिसती जनता को बड़ा गर्व है।

दूसरा यह था कि जिस फोटो कापी के आवेदक से रुपए मांगे जा रहे हैं। वह सरकारी कर्मचारी, अधिकारी फोटो कापी के रुपए 1.50 तो जब में रखेगा और शासन को बिल रुपए 2/- का लगाकर रुपए 1.50 का भ्रष्टाचार का सुअवसर और आवेदक को लूटने की कानूनी व्यवस्था तो भ्रष्टों ने अधिनियम लागू होने के साथ ही कर दी थी। तीसरा अवलोकन के रुपए 50/- प्रति घंटा बाद में 17-09-05 हुए। केंद्र शासन के पेंशन व व्यक्तिगत समस्या निवारण मंत्रालय ने भले ही मूल कानून में संशोधन कर रुपए 5/- प्रतिघंटा किए जिसे किसी भी राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कार्यालयों ने आवेदक को आर्थिक क्षति पहुंचाने, मानसिक प्रताड़ना देने सूचना न दिखाने और देने के उद्देश्य से नहीं माना, जबकि आवेदक अपनी कीमती वक्त भी खर्च करता है।

इस अधि. 05 की परिभाषाओं की धारा 2 (न) में तृतीय पक्षकार से तात्पर्य (देश का) नागरिक न होने से है। किसी भी विदेशी नागरिक को सूचना देने को तृतीय पक्ष माना जाएगा के विपरीत केंद्र व राज्य सूचना में बैठे भ्रष्टों की फौज ने भी मनचाही व्याख्या कर आवेदकों को सूचना देने से अधिकांशतः सीधा मना कर दिया, जिसे न केवल केंद्रीय सूचना आयोग वरन राज्यों के सूचना आयोगों ने भी मनचाही व्याख्या कर मुहर लगा दी।

पूरे देश के भ्रष्ट खुदाओं, पहले इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी और दूसरे उच्चतम न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों में बैठे न्यायाधीशों ने कदम-कदम जो स्वयं राष्ट्र में कानून व न्याय व्यवस्था को संभालने, जनता का विश्वास जमाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं इस अधिनियम की न केवल कदम-कदम पर्याप्त धज्जियां उड़ाई, सिरे से नियमों, कानूनों की व्याख्या कर सिरे से खारिज कर दिया, वरन मौका मिलने पर पद के बल पर बलात्कृत उषमं दुराशयपूर्ण मानसिकता से संशोधन कर दिए, ताकि कोई भी नागरिक इन भ्रष्टों के दुष्कृत्यों को जानकर इनकी सच्चाई, भ्रष्टाचार, कुकर्मों को सार्वजनिक न कर दे, जबकि सच यह है कि ये किसी भी

कानूनी संशोधन करने के पात्र नहीं हैं। जिस विधायिका ने यह कानून बनाया वह ही इसमें संशोधन की पात्र है।

इन सबके साथ में राज्यों में नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त व आयोग में पूरे देश हर राज्य आयोगों में महाभ्रष्ट और निकम्मां की फौज को बैठाया गया जो हर कदम-कदम जालसाजीपूर्ण मानसिकता से न केवल ओतप्रोत हैं वो अपनी वसूली के लिए उल्टे ही बहुविधि प्रताड़ित करने बार-बार चक्कर लगवाने, फंसला हो जाने के बाद भी महीनों निर्णय की प्रतियां जानबूझकर न भेजते वसूली कर लेने के कारण निर्णय देने के बाद भी न साइटों पर लोड करती हैं।

म.प्र. राज्य सूचना आयोग में सारे ऐतिहासिक भ्रष्टों को ऐसी फौज बैठाई गई है। मु.सु.आ. पी.पी. तिवारी, आयुक्त इकबाल अहमद दोनों पूर्व के इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के सेवा निवृत्त अधिकारी रहे हैं। तिसरे दिनेश जुगरान पुराने इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस का अधिकारी है। स्वाभाविक है इन तीनों के खून में भ्रष्टाचार औप्रे मक्कारी भरी है। चौथे आयुक्त महेश वाजपेयी पत्रकार हैं तो इन्हें यह भी मालूम कि एक जिलाधीश के अंतर्गत एक जिले में कितने विभाग आते हैं। शायद आंगलाभाषा भी इनकी कमजोर है। एक जिलाधीश के अंतर्गत 70-80 शासकीय विभागों, निगमों का नियंत्रण होता है। इसके विपरीत इन्हें 9-10 विभाग ही दिखे, इसलिए इन महोदय ने देवास जिले के जिलाधीश को मात्र 4 विभागों की जानकारी देने को लिखा, शायद ये भी प्रशासनिक पद पर पहुंचते ही शासकीय भ्रष्टाचार के वायरस से संक्रमित हो चुका है। इसलिए स्पष्ट अपील होने के बाद भी न तो ये स्पष्ट आदेश के साथ दंड कर पा रहे हैं। बेशक इन चारों पर शासन का, मंत्रियों का भी भारी दबाव है। इसलिए इन आयुक्तों ने 2-4 को छोड़कर अभी तक रुपए 25000/- का दंड भी किसी पर नहीं ठोका है। भ्रष्ट अधिकारियों को वैसे इन सबसे कोई असर नहीं पड़ा है, तो एक टुकड़ा ज्यादा डालने लगे सूचना आयोग के नाम का।

भ्रष्टाचार से कमाई के आधार पर पदस्थापनाएं

म.प्र. में स्वास्थ्य विभाग में कदम-कदम व्याप्त भ्रष्टाचार और वसूली के समाचार हर रोज दैनिकों में हमारे प्रबुद्ध पाठक पढ़ते ही हैं। इससे संबंधित विभाग जो अति महत्वपूर्ण तो हैं वहां के निरीक्षक चाहे वो खाद्य का हो या औषधि में दोनों हाथों से भरपूर करते हैं। इस विभाग में पदस्थापनाओं से लेकर स्थानांतरण रुकवाने तक में लाखों की कमाई स्वास्थ्यमंत्री, स्वास्थ्य सचिव और इस विभाग का नियंत्रक भी खुलकर करता है।

सूचना के अधिकार में म.प्र. के स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत म.प्र. औषधि एवं खाद्य अपभ्रिण्य विभाग से जो सूचनाएं मांगी गई थी स्वाभाविक था कदम-कदम भ्रष्टाचार से भरे होने के कारण जानकारियां भी जालसाजीपूर्ण तरुके से दी गई थी। फिर भी जो जानकारियां हाथ लगी हैं उनका ही प्रकाशन हम अपने प्रबुद्ध पाठकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। जिससे पाठक ये जान पाएं कि जिन जिलों में ज्यादा कमाई की संभावनाएं हैं वहां एक-एक जिले में 5-5 खाद्य एवं औषधि निरीक्षक वर्षों से जमें बैठे हैं। जहां कमाई की संभावनाएं कम हैं वहां अधिकांश छोटे जिलों के प्रभार दो जिलों के एक ही खाद्य व औषधि निरीक्षकों को दे रखे हैं। वैसे वर्तमान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक श्री अगनानी की कार्यशैली से विभाग में चारों तरफ दहशत है, परंतु इसके विपरीत इन्होंने इंदौर के एक औषधि निरीक्षक जिसके पास दवा बाजार का प्रभार था, निलंबित तो किया परंतु उससे दवाबाजार का प्रभार नहीं लिया गया तो उक्त औषधि निरीक्षक ने भी इस निलंबन का फायदा उठाते हुए वसूली की गति दुगुनी कर दी, त कि कल के दिन कोई जिम्मेदारी आई भी तो बड़े ही सहज ढंग से निलंबन अवधि का बहाना लेकर बच निकलेगा। जबकि नियंत्रक श्री अगनानी को इसे निलंबित करने के साथ ही इससे प्रभार लेकर तुरंत दवा बाजार में बाहर के औषधि निरीक्षकों की पूरी टीम भेजकर जांच करवानी चाहिए थी, ताकि इस निलंबित औषधि निरीक्षक के खिलाफ ठोस दस्तावेजी सबूत इकट्टे कर आरोप पत्र तैयार करने में सुविधा मिलती, परंतु नियंत्रक अगनानी की ये लापरवाही उन्हें आने वाले समय में भारी महंगी पड़ सकती है। क्योंकि निलंबित औषधि निरीक्षक भारी शातिर है। इसलिए वर्षों से दवा बाजार का प्रभार थामे बैठा था।

घर में बीवी का, देश में सोनिया का, विश्व में अमेरिका का सिंग इज स्लेब नॉट किंग गुलामों की औलाद है, गुलाम रहेगा, गुलाम रहेगा

अभी हाल ही में प्रदर्शित फिल्म सिंग इज किंग से मनमोहनसिंह अपने आप को व उनका कांग्रेस व संग्रम के अन्य राजनैतिक अपराधियों का गिरोह उसे किंग बता रहा है। वास्तविकता से सिंग इज स्लेब नॉट किंग। अर्थात्, सिंग राजा नहीं गुलाम हैं। स्वयं के घर में बीवी का केंद्र की सत्ता में सोनिया का और विश्व में अमेरिका का।

केन्द्रीय सत्ता में तो वह जालसाजी का ही किंग रहा, अपनी जालसाजियों से राष्ट्र की जनता को महंगाई, आतंकवाद, जातिवाद देकर भी अपने आप को मक्कार, किंग कहता है, लानत है इस धूर्त राज को। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि सिंग इज स्लेब नॉट किंग, जो विदेशी, मक्कार, शातिर एजेंट सोनिया के लिए अपने ही देश को विदेशियों को गिरवी करने, बेचने पर तुला है। ठीक है इस देश में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए गधे को भी बाप बोलने की प्रथा रही है, तो सत्ता के सफेदपोश अपराधी इसे राजा ही क्यों, भ्रष्टाचार का धूर्त सम्राट भी कह सकते हैं, दूसरा यही कारण था कि हम गुलामों की औलाद, गुलाम ही रहना पसंद करते हैं। तो गुलामों का क्या फर्क पड़ता है कि सिंग किंग है या सोनिया अम्मा या बुश इस देश का विधाता है, गुलामों को तो किसी की भी गुलामी करना है, दो वक्त की रोटी खाकर जो बेगार टालनी है टाल रहे हैं और पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं। परमाणु समझौते से जो धूर्त मनमोहन पूरे देश के सामने अपने आप को किंग के रूप में प्रस्तुत कर

रहा है। उसकी असलियत भी हमारी समय माया व करप्शन की साइटों ने 6-9-08 को ही पूरी दुनिया का रात्रि 8.45 पर बता दी थी और सारे यूरोप और एशिया के मीडिया ई-मेल से संदेश भेज दिया था ये रुपए 6000 अरब का सौदा है जिसमें अकेले मनमोहन कमीशन का गुलाम रुपए 600 अरब का कमीशन डकारेगा, रही जहां तक बिजली की बात तो वो अमेरिका है, जब देखलेगा कि हम पूरी तरह उस पर निर्भर हो गए हैं तो फिर हमें ब्लेकमेल कर अपनी मनमानी कीमतें वसूल करेगा, जब मनमोहन रुपए 600 अरब का कमीशन डकारेगा तो स्वाभाविक है उसकी अम्मा सोनिया भी रुपए 600 अरब डकारेगी ही। कैसा किंग है या गुलाम अंदाज लगाएं पाठक।

जनसंख्या वितरण का आँकड़ा

Table with 7 columns: S.N., पदस्थान एवं अधिकारी/ अधिकारी का नाम, पद, पदस्थान, राज्य, उ.स. में पदस्थापना का तिथि, पदस्थापना का तिथि, पदस्थापना का तिथि

नियंत्रक खाद्य व उपसंचालक, नापतौल से खुला सपोर्ट

लीटर से गैस बेचना

पूर्णतः अवैध

राष्ट्र में कोई कानून नहीं लीटर से गैस बेचना का इंदौर। इस महानगर में लूटने के तरीकों और वसूली में सरकारी अधिकारी और निजी दुकानदार, वाहन गैस विक्रेता सब चोर-चोर, मौसरे भाई की तरह एक है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गैस पंप विक्रेताओं का, जो नियम कानून विरुद्ध लीटर से गैस बेचकर 30 से 50% तक कमाई कर रहे हैं।

गैस को लीटर से नहीं बेचा जा सकता, यह नापतौल निरीक्षक भी मानते हैं। न ही गैस जैसी उड़नशील, शीघ्र वाष्पित होने वाली वस्तु को लीटर से बेटा जा सकता है। उसे भरते समय किलोग्राम में ही तोला जाना चाहिए, इसके लिए पहले गाड़ी का वजन लेकर, जितनी लेना है वजन से तोलकर दी जाना चाहिए।

1 किलोग्राम और 1 लीटर में 300 से 400 ग्राम का अंतर आता है। अर्थात् प्रति किलोग्राम के पैसे लेकर लीटर से देने में 30 से 40% तो वैसे ही गैस कम दी जा रही है फिर उसमें साधारण वायु मंडलीय गैस भी 10 से 20% मिला दी जाती है। जो जलते समय उड़ जाती है। इस प्रकार आसानी से गैस पंप विक्रेता 40 से 60% तक की कमाई कर रहे हैं।

**पंप विक्रेता
चुकाई
कीमत का
५० से
६०% माल
ही दे
रहा**

अधिकांश छोटी नगरसेवा या सिटी वैन वाले गैस के उपयोग से भारी हानि का सामना कर रहे हैं। उन्हें पेट्रोल से ज्यादा महंगी पड़ रही है। रु. 32 रु. प्र.कि. की गैस को लीटर से देने पर वाहन चालकों को माल मिल रहा है मात्र रु. 16 से 20 तक, तीन वर्षों से चल रहे गैस पंपों के इस नाटक, लूट और वसूली को न, तो नाप तौल विभाग रोक पा रहा है, न ही जिलाधीश। साथ ही महानियंत्रक नापतौल के पास भी पिछले तीन वर्षों में सिटी वैन एसोसिएशन ने अनेक शिकायतें भेजी है क्षेत्रीय उपसंचालक/नियंत्रक,

नापतौल को लिखकर दी है, परन्तु इस हरामखोर गैस पंप मालिकों पर इस गैर कानूनी कार्य के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

या यो कह लीजिए कि नापतौल के निरीक्षकों को जो वसूली पेट्रोल पंपों से मिलती थी शायद उसकी दुगुनी वसूली गैस पंपों से मिल रही है। इसलिए तो श्रावण की फौज कैसे कोई कार्यवाही कर पाएगी। जहां तक नए जिलाधीश राकेश श्रीवास्तव का सवाल है, तो वह रा.प्र.से से घन देकर मा.प्र.से. में आया है। फिर वहां से घन देकर, रायल्टी पर इंदौर में बैठाया गया है, तो यह भी आया तो वसूली करने ही है। तो इस हरामखोर, भ्रष्ट से अपनी नहीं संभल रही है, जो कि नगर ने, देश ने और दुनिया ने ये बात कर्णपूर्व में देखी है। हाय भ्रष्टाचार तेरा आसरा।



पेट्रो उत्पादों की बढ़ती/ बढ़ाई जाती कीमतें प्रीमियम के नाम पर पेट्रोल कं. की लूट

हमारे राष्ट्र में वर्तमान में सभी मुख्य कंपनियां सरकार के आधीन हैं। हिन्दुस्तान, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, तीनों अपने-अपने पेट्रोल पम्पों पर जो ब्रांडेड पेट्रोल बेच रही हैं। तीनों ने कहीं भी जनता को ये नहीं बताया कि आखिर एक्स्ट्रा माइलेज प्रीमियम जैसा पेट्रोल कितने आक्टेन का है। जबकि साधारण पेट्रोल 60 आक्टेन का होना चाहिए। तो ये ब्रांडेड जिसकी कीमतें रुपए 3 से 4 रुपए तक ज्यादा वसूली जा रही है। उपभोक्ता को क्या अधिक फायदा दे पा रही है, जिस माइलेज का ये गुणगान कर रही है हमारा दावा है कि लाखों उपभोक्ता जिनसे रुपए 3-4 ज्यादा वसूला जा रहा है। 60 कि.मी. का औसत इस ब्रांडेड पेट्रोल का उपयोग करने से देने लगी है। अधिकांश का उत्तर न में आया है। अर्थात् ब्रांडेड के नाम पर प्रीमियम, पावर से पैसे भर वसूले जा रहे हैं।

साधारण पेट्रोल में 60 आक्टेन की ऊर्जा होना चाहिए जो कि कोई भी कंपनी 35-38 से ज्यादा नहीं दे रही है। तो जो पावर सी प्रीमियम या अन्य नामों से रुपए 54 के स्थान 58 रुपए प्रति ली. बेचा जा रहा है क्या 70 आक्टेन का है ये कुछ भी बताने को तैयार नहीं, इन हरामखोर कंपनियों के इंदौर में मांगलिया स्थित डिपो प्रबंधक को सूचना के अधिकार में पत्र दो भी तो ये भ्रष्ट शूकरों की फौज उसे बंबई भेज देती है। एक कापी आपको देकर इतिश्री कर लेती है। पेट्रोल पम्प मालिकों से पूछो तो ये भ्रष्ट बोल देते हैं। हमें कुछ नहीं मालूम कंपनी से पूछो। इसके विपरीत सच यह भी है कि इन हरामखोर पेट्रोल पम्प मालिकों और डिपो इंचार्ज, विक्रय प्रबंधकों का गहरा गठजोड़ चलता है। भ्रष्टाचार के पैसे में क्योंकि जो जहां बैठा है लूटने में लगा है, डिपो प्रबंधक जहां एक ओर पेट्रोल पम्प मालिकों से पूरा पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं करते हर बार टैंकर भरने में 100-200 ली. पेट्रोल की हेराफेरी की जाती है। यही कारण है कि पूरे मांगलिया में पेट्रोल का अवैध व्यवसाय चलता रहता है।

स्वभाविक है पेट्रोल पम्प मालिक ये घाटा पूरा करने के लिए ग्राहकों की जेब से ज्यादा वसूली के बाद भी कम पेट्रोल नापकर घाटा पूरा करेगा। दूसरी ओर पेट्रोल पम्प मालिकों और विक्रय प्रबंध के साथ ही इस पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति में जिम्मेदार नागरिक आपूर्ति विभाग भी इस लूट को पूरी छूट दे रहा है, क्योंकि इस बहाने इस विभाग के खाद्य निरीक्षकों से लेकर खाद्य नियंत्रक परमार को भी मोटी प्रीमियम और पावर अलग से पम्प मालिक भुगतान कर देते हैं। तो वो हरामखोरों की फौज भी क्यों कुछ बोलेगी।

कम नाप व मिलावट की

पूरी छूट

खाद्य व नापतौल निरीक्षकों को महीना मिलता है

इंदौर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से पूरे देश और विश्व की जनता परेशान हो ही रही है। तो दूसरी तरफ पेट्रोल पम्पों पर काम नाप, पेट्रोल चोरी के साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल में मिलावट के खेल को न को कंपनियों रोकना चाहती है न ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का पूरा स्टॉक जिसमें खाद्य निरीक्षकों से लेकर सहा. खाद्य आपूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य नियंत्रक, अधिकारी बैठे हैं ये सारा स्टॉक मिट्टी के तेल, पेट्रोल-डीजल में मिलावट की पूरी छूट देता है, क्योंकि इन हरामखोर निरीक्षकों के पास जितने पेट्रोल पम्प बंधे हैं या इनके अधीनस्थ है ये सब हरामखोर निरीक्षक साह. खाद्य आपूर्ति अधिकारी से लेकर जिला अधिकारियों तक सबको महीना मिलता है, इसलिए ये हरामखोर पिछले कई वर्षों से पेट्रोल और डीजल के नमूने ही नहीं लेते हैं। ये हाल न केवल इंदौर के पेट्रोल-डीजल पम्पों का है, वरन् उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, के साथ भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर से प्राप्त जानकारी का भी है। न ही वहां के जिलाधीशों के पेट्रोल पम्पों पर मिलावट से कोई मतलब है न उसको गुणवत्ता से। ये हाल छोटे शहरों में कुछ ज्यादा ही है और राजमार्गों की हालत और भी दयनीय है। वहां दूरस्थ क्षेत्रों में तो खुले में पेट्रोल पम्पों पर मिट्टी का तेल, हेवजीन और साल्वेंट मिलाकर ही वर्षों से बेचा जा रहा है। बेरोकटोक किसी को कोई परवाह नहीं है, फिर जब पेट्रोल पम्प फाला हर माह इंदौर में रुपए 5000/- निरीक्षकों को देगा तो रुपए 50 हजार तो कमाएगा ही न क्योंकि उसे न केवल खाद्य निरीक्षकों से लेकर खाद्य जिला अधिकारी को बांटना है, वरन् क्षेत्र के थाना इन्स्पेक्टर की गाड़ियों, जिलाधीश और उनके लम्गुओं, भग्गुओं, क्षेत्र के विधायकों को भी मुफ्त या घटी दरों पर पेट्रोल डीजल बांटना है तो कहां से लाएगा। स्वाभाविक है जनता की जेब ही काटना और पेट्रोल डीजल में मिलावट करना ही पड़ेगी। इसके अतिरिक्त ये जिला मजिस्ट्रेट ये मंत्रीजी के साले हैं वो बहनोई हैं को भी झेलना है तो मिलावट के साथ जनता को कमनाप भी देना पड़ेगा। तब ही तो न केवल खर्चा निकलेगा, वरन् पेट्रोल पम्पों के साथ मालिकों के अनेकों अवैध कारोबारों, काला धन भी इकट्ठा किया जा सकेगा। यही प्रक्रिया नापतौल निरीक्षकों व पूरे विभाग की है, यहां बैठे पूरे प्रदेश के हरामखोर को भी पेट्रोल पम्प मालिक महीना बांटते हैं। स्वाभाविक है उसे क्या मतलब फिर कि वो ली. पर 50ग्राम मार रहा है या 200 ग्राम या कार के 10 ली. में से पूरा लीटर ही मार रहा है। इन धूर्त रिश्तखोर, सफेदपोश, डकैत विभागों को यदि सूचना के अधिकार में पत्र दो तो आवेदकों को डराने, धमकाने से लेकर ये हर प्रक्रिया अपनाते हैं। सूचना न देने के लिए जिनके बारे में समय माया पिछले दो वर्षों से छाप रहा है।

जन धन का उपयोग चुनावी प्रचार में

म.प्र. जनसंपर्क के अधिकारियों का भ्रष्टाचार, अपनों को रेवड़ी का ऑफर

भोपाल। म.प्र. जनसंपर्क में मचे भ्रष्टाचार के तांडव को कोई समाचार पत्र विज्ञापन समाचार श्रृंखलाएं, इंटरनेट साइट्स कोई उजागर नहीं करते, क्योंकि वहां हर समाचार पत्र, दूरदर्शन के समाचार चैनल्स, इंटरनेट वेबसाइटों के प्रबंधकों के वहां पर बैठे अधिकारियों से लेना-देन के संबंध बने हुए हैं। जिनसे संबंध है फिर तो कैसे भी हो, उनकी प्रसार संख्या कितनी भी हो केंद्रीय दरें कितनी भी हो उन्हें बेरोकटोक विज्ञापन मिलता है, जनता के धन की ये लूटमार तो वहां बैठे भ्रष्टों का गिरोह जिसमें आयुक्त मनोज श्रीवास्तव से लेकर, लाजपत आहूजा व अन्य सभी वर्षों से करते आ रहे हैं; यही कारण है, कि वहां बैठी धूर्तों की फौज कभी किसी को सूचना के अधिकार में

जवाब देने की अपेक्षा शब्दों का मायाजाल बिखेर कर उल्टे-सीधे कई गुना ज्यादा शुल्क बताकर ये हरामखोर डरा-धमकाकर आवेदकों को चलता कर देते हैं।

जहां तक आयुक्त मनोज श्रीवास्तव का सवाल है तो ये शातिर बंदा जो कि पूर्व में इंदौर का ही जिलाधीश था, इसके भ्रष्टाचार के किस्से कॉलोनाइजर्स के साथ जुगलबंदी, कांग्रेसी नेताओं के साथ भारी भ्रष्टाचार किए। बेशक ये आयुक्त महोदय का पुराना कारोबा है कि प्रदेश के मुखिया की हां में मिलाकर उसकी आड़ में अपने झाड़ खड़े करो, अब जबकि चुनाव सिर पर है, दोनों हाथों से म.प्र. विकास रथ व जन आशीर्वाद के नाम पर जो कि विशुद्ध भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। जनता के

धन को इस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। बेशक इस कार्यक्रम में करोड़ों रु. के वारे-न्यारे वहां बैठे शूकरों की फौज डकारेगी।

इका छोटा सा उदाहरण यह है कि 230 विधानसभा क्षेत्रों में चलाए जा रहे इस म.प्र. विकास रथ में एक-एक रथ चलवाया जा रहा है। जिसका मासिक किराया रु. 1,45,000 प्रति माह है और ये दो माह के लि म.प्र. जनसंपर्क विभाग के अधिकारी लाजपत भाटिया की गोपनीय और सुप्त समझदारी में फोर्सविजन नाम की संस्था चला रही है। अर्थात् ये सौदा रु. 6 करोड़ 17 लाख का है, पर है, दोनों हाथों से म.प्र. विकास रथ व जन आशीर्वाद यात्राओं के नाम पर जो कि विशुद्ध भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। जनता के

दूसरा मुख्यमंत्री ने 8 सितंबर 08 से उज्जैन के महाकाल से जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत की है। ये जन आशीर्वाद भी वोटों और सत्ता प्राप्ति का आशीर्वाद होकर विशुद्ध राजनैतिक कार्यक्रम है। जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क के साथ जनाकर्षण कार्यक्रम ही है, जिसमें जनता के इरादों की टोह लेना ही है। इस कार्यक्रम में भी सारा पैसा जिसमें भीड़ इकट्ठी करने से लेकर भीड़ का परिवहन, भोजन पानी का कार्यक्रम, शासकीय अधिकारियों को एकत्रित करने उनसे जनसमस्याओं की जानकारी उनका निराकरण करवाने, जन आक्रोश खत्म कर, सत्ता के पक्ष में मतदान करने का ही कार्यक्रम है। इसमें भी पैसा जनसंपर्क अधिकारियों के माध्यम से ही खर्च किया जा रहा

है जो शासकीय पैसा है। स्वाभाविक है ऐसे कार्यक्रमों को संपन्न कराने में अगर रुपया खर्च होता है तो रु. 4 के बिल लगाए जाते हैं। बाकी के रु. 3 की बंदरबांट आयुक्त से लेकर नीचे तक बैठे भ्रष्ट फौज डकार जाती है। इस संबंध में हमारे

भोपाल प्रतिनिधि श्री एस.के. भारद्वाज ने एक आवेदन सूचना के अधिकार में विभाग को दे दिया है। जिसमें जानकारी के स्थान पर उल्टे-सीधे ही जवाब दिए जाना है, जैसा कि इस हरामखोर विभाग का पुराना इतिहास रहा है।

विकास रथ व जन आशीर्वाद के नाम करोड़ों का खर्च

**रमजान मुबारक
बेरायती
हार्डवेयर सेंटर**

उच्च क्वालिटी, आधुनिक एवं
सभी स्तर के थोक व फुटकर
हार्ड वेयर विक्रेता

L4, जवाहर मार्ग, (मोहम्मदी मार्केट)
पटेल ब्रिज के पास, इंदौर
फोन - (ऑ.) 2476147, 2364068
(नि.) 2366169, फेक्स 0731-2476147

रिजर्व बैंक की गृह ऋण दरों पर ब्याज दर बढ़ाने की नौटंकी

महंगाई कम करने के कांग्रेसी शिगूफे जनता से कार-गृह ऋण ब्याज दरें बढ़ाने से बैंकों का लाभ ही बढ़ेगा



भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा, दिए जाने वाले कार व गृह ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ाने से जिन लोगों ने कार व गृह ऋण ले लिए हैं। उनका ही बजट बिगाड़ा है, जहां तक नए गृह ऋण और कार ऋण लेने का सवाल है तो उपभोक्ताओं की संख्या भर कम हो जाएगा, वैसे बढ़ती पेट्रोल की, डीजल की कीमतों से स्वयं उपभोक्ता कार ऋण लेने से हिचकिचाने लगे हैं। गृह ऋणों में भी न केवल

ब्याज दरें बढ़ने से वरन सीमेंट, लोहा व अन्य सामग्री के साथ ही मजदूरी बढ़ने से वैसे भी अपने मकान व छत का सपना चकनाचूर होने लगा है। फिर दो नं. के काले धन वाले तो दिखावे और आयकर बचाने के लिए ही गृह ऋण लेते हैं। ताकि उन्हें दो नं. के काले धन को एक नं. में परिवर्तित करने में कानूनी परेशानी न आए, फिर रु. 10-20 लाख का ऋण लेना दिखा कर करोड़ों

भी खर्च कर दें, तो भी कोई अंगुली उठा सके।

अब रहा महंगाई का सवाल तो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक के रेपो, रेट बढ़ाने सी.आर.आर. बढ़ाने से खाद्यान्नों, तिलहनों, दलहनों, के व्यापारी ब्याज दर बढ़ने से जमाखोरी तो करेगा साथ में जनता से इन वस्तुओं पर दिए गए ब्याज की दरें भी वसूलेंगे तो महंगाई तो उल्टा ही बढ़ेगी जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने का सवाल है, तो रिजर्व बैंक बेशक बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित करने में सक्षम है, परंतु भारत का ये केंद्रीय बैंक, भारत के केंद्रीय शासन के वित्त

विभाग के अंतर्गत कार्यकरण है, भारत में वर्तमान वित्त मंत्री के निर्देश पर कार्य करता है।

हमारे वित्त मंत्री जानबुझकर अरबों रु. की कमीशन खोरी कर रही है, इसलिए ये धूर्त जनता और मीडिया की नजरों में मिर्ची झोंक कर कमीशन उकारने के लिए भ्रमित कर रहा है। जिस दिशा में काम करना चाहिए उस दिशा में समय माया के इतने बार प्रकाशित करने के बाद भी कोई भी कार्य नहीं किया गया, महंगाई के हल्ले को समाप्त करने के लिए आतंकवादी घटनाओं का आंजमा दे दिया गया। रिजर्व बैंक को निर्देश देकर रेपो रेट, ब्याज दरें घटा बढ़ा दी गईं, परंतु

वास्तविक कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे आई.सी.सी जो कि ब्रिटेन की ब्रिटिश बैंकों कं. की भारत में 60 वर्ष से संलग्न कंपनी बन कर बैठी हैं पर नियंत्रण लगाने की बात नहीं की जा रही जो खुले में मंडी के पहले ही किसानों से सभी प्रकार की फलें अपने चौपाल में भंडारगृहों पर खरीद लेती हैं। इसके बाद में हर फसल को अपनी मनमानी कीमतों पर सोचती है।

ऐसी सैंकड़ों कंपनियों के सीधे किसानों सफल खरीदने पर भंडारण करने पर, उनकी खरीद को बैंकों द्वारा दी जा रही बैंक साख पर प्रतिबंध

लगाया जाना चाहिए, जान-बुझकर चीट अंबरम इन सबसे मोटा कमीशन खाकर, जनता की जमाओं से इन बढ़ी कंपनी, व्यापारियों को बैंकों से नगदी उपलब्ध करवाकर कृषि उत्पादों की जमाखोरी करने का अवसर देकर सभी खाद्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करता रहा है। अपने इन कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए कार व गृह ऋण ब्याज दरों की घटाने-बढ़ाने नौटंकी दिखा रहा है, मीडिया में बैठे मुखेदों को चाहे तो इकानामिक टाइम्स हो या वित्तीय प्रकाशन सच को कोई ध्यान नहीं छापना चाहता।

भारतीय अर्थ शास्त्रीयों, वित्त मंत्रालय प्रधान मंत्री सब केवल घड़ियाली आंसु बहाकर जनता को भ्रमित कर अपनी कमीशन खोरी और लूटपाट में लगे हैं। वास्तविकता में तो किसी को कोई मतलब नहीं महंगाई कम करने से रिजर्व बैंक की इन थोथी। बचकानी चालों से आंसु नहीं पोछें जा सकते।

बीओटी, रा.रा. मार्गों की नीलामी वाहनों से वसूली का षड्यंत्र म.प्र. सड़क भ्रष्टाचार विकास वसूली निगम

सड़कों की गुणवत्ता के नाम पर वैधानिक लूट, वसूली

म.प्र. में वर्तमान भाजपा की सरकार लूट वसूली और भ्रष्टाचार के कुछ प्रकरों, विभागों में कांग्रेसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी दानव के नक्शे कदम पर चलते हुए जनता से नौच खसोट कर दीर्घकालीन तांडव कर रही है। इस कड़ी में वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण है, सड़कों पर बीओटी के अंतर्गत ठेके देकर नाकों के माध्यम से वसूली करने के 15 से 30 वर्ष के ठेके दिए जा रहे हैं।

दिग्गीदानव के खास चले वर्तमान भाजपा के लो.नि.वि. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इन षड्यंत्रों को अंजाम देने में भरपूर ऊर्जा लगाकर कई गुना ज्यादा लागत दिखाकर सड़कों की नीलामी कर गिरवी करने पर तुले हैं जिसमें हाल ही में सम्पन्न किए गए लेबड़ रतलाम, नयागांव, ब्यावरा मार्ग के साथ इंदौर-उज्जैन राजमार्ग को भी नीलाम कर गिरवी करवा

पेज 8 से जारी

स्वाभाविक है जनता की वर्तमान और भावी पीढ़ी को क्यों ये सड़क पर चलने लायक नागरिक भी क्यों बनाएंगे, यदि ये सभ्य नागरिक बन गए तो इनके काले कारनामों की जनता को समझ आ जाएगी। इसलिए इसके विपरीत जो भावी विद्यालयों में जो वाली पीढ़ी को यौन शिक्षा देकर अवश्य उन्हें शैशवावस्था में ही बर्बादी की राह दिखाकर उसके धिनौने कृत्यों में उलझाना चाहती है, ताकि जनता सत्ता के शीर्ष पर बैठे धूर्त गिरोहबाजों की राष्ट्र और जनता के भविष्य की बर्बादी के इनके कुकर्मों पर कभी ध्यान न दे सके।

सड़कों पर 5 लाख क्यों 50 लाख मरे इनकी बला से, कल के मरते आज मरें, ताकि उनकी चिताओं पर घड़ियाली आंसु बहाकर उनका बीमा भी डकार सके, हंगामा कर सके, जनता और मीडिया का ध्यान वास्तविकताओं से हटाकर उनके परिजनों के आंसू बहाने में खो जाएं, ये है हमारे 60 वर्ष की आजादी की सबसे बड़ी उपलब्धि धन्य है, कर्णधारों।

दिया गया है। जबकि इसी मार्ग पर रुपए 6 करोड़ हाल ही में मार्च-अप्रैल में खर्च कर इसकी मरम्मत की गई थी। बेशक इंदौर लो.नि.वि. संभाग-2 के भ्रष्ट जालसाज का.अ. राणे ने मात्र 2 करोड़ का ही कार्य करवाया था तीन महीने में ही उसके फिर 10 दिन पहले गड्डों पर मरहम पट्टी की गई है। की जा रही है। इस मक्कार भ्रष्ट के पूरे सेवाकाल में इसने कदम-कदम जालसाजियों से खुलकर न केवल भ्रष्टाचार किया वरन अनेकों जांचों, उच्चाधिकारियों को भी उसने आरक्षित वर्ग में होने का लाभ उठाकर कभी कोई परवाह नहीं की।

इंदौर-उज्जैन मार्ग में इंदौर से लेकर 37 कि. तक इसने रुपए 4 करोड़ और 37 से 55 तक उज्जैन में का.अ. के.लक के निलंबित होने के बाद का.अ. आर.के. सलूजा ने रुपए 2 करोड़ खर्च किए इसके बाद भी समय माया की लगातार निर्माण और मरम्मत की स्तरहीन गुणवत्ता, दोनों तरफ की 5'-5' की कच्ची मुम के संबंध में लगातार रिपोर्ट छापी जाने के बाद कुछ कि.मी. में ही भराई की गई। जबकि पट्टियों की दोनों ओर की भराई के बंदों ने पूरे बिल भुगतान जरूर किए, परंतु भराई नहीं करवाई गई। इस विभाग का सचिव इंडियन एक्सप्रेस सर्विस अधिकारी पी.डी. मीना जो पूर्णतः गैर तकनीक अधिकारी है न तो उसे सिविल इंजीनियरिंग की अ,ब,स,द आती है, चूँकि आई.ए.एस. है, सचिव है, तो फिर आरक्षित वर्ग से है इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्या जरूरत है विभागीय कार्य पद्धतियों नियमों, कानूनों का अध्ययन करने की जो ये कहे वो कानून, स्वाभाविक है, का.अ. राणे जो पट्टी पढ़ाई, सचिव व महोदय को वही गागरौनी बोलना था, वही बोली।

चार लाईन मार्ग बनाने के जब विभाग को रुपए 1 से 2 करोड़ क्षेत्र के स्टेटा के अनुसार मिलते हैं तो फिर लेबड़-रतलाम 125 किमी सड़क को रुपए 76 करोड़ में अर्थात् 6.10 करोड़ रुपए प्रति किमी, नयागांव-

ब्यावरा 179 कि.मी. रुपए 725 करोड़ में क्यों ठेकेदार को चार लेन मार्ग बनाकर अनाप-शनाप वसूली के लिए अप्रैल -08 में सौंपा गया। जबकि वहीं काली चिकनी मिट्टी के इंदौर-उज्जैन 49 किमी को लगभग रुपए 100 करोड़ में चार लेन बनाने के लिए गिरवी कर इसी म.प्र. सड़क विकास निगम के धूर्त सुलेमान ने जून में समझौता किया जो लगभग रुपए 2 करोड़ प्रति कि.मी. की दर से दिया गया। इस बात से इस निगम की जालसाजियों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां काली मिट्टी के क्षेत्र में सड़क निर्माण में 6-1 प्रति किमी से 6.25 करोड़ प्रति किमी सड़क निर्माण जबकि दोनों ही 4 लेन मार्ग है। में किए गए अनुबंधों में कितनी भारी लूट-खसोट और कमीशन बाजी की गई है तो मात्र उस पर से गुजरने वाले वाहन चालकों से जबकि राज्य शासन हर ली. पेट्रोल पर रुपए 20 व डीजल पर रुपए 12 प्र.ली. लगभग विक्रय कर वसूल रहा है, जितना पेट्रोल डीजल पर वाणिज्यकर

वसूला जा रहा है, उसके मात्र 25% से कम में भी बेहतरीन सड़कें जनता को उपलब्ध करवाई जा सकती है। म.प्र. शासन में बैठे मुख्यमंत्री शिव चौहान लो.नि.वि. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रधान सचिव पी.डी. मीणा, म.प्र. सड़क भ्रष्टाचार विकास निगम का सुलेमान की धूर्तताओं और भ्रष्टाचार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां पूरे भारत की राज्य सरकारें अधिकांश महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका प्रबंधन केंद्रीय भूतल पोत परिवहन मंत्रालय को सौंप कर अपनी जिम्मेदारियां व खर्चों से मुक्ति चाहते हैं। वहीं म.प्र. शासन के उपरोक्त वर्णित भ्रष्ट धूर्तों ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय से इंदौर-भोपाल रा.रा. क्र. 89 इंदौर-कोटा, इंदौर-रतलाम नयागांव ब्यावरा, नीमच जैसे अंतरराज्यीय मार्गों से मात्र ठेकेदारों को सौंपकर वसूली करने के राष्ट्रीय राजमार्गों में श्रेणीबद्ध होने के बाद भी जबरन छीना गया, यह बात दिल्ली में भूतल परिवहन मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों की सभा में हर बार उठाई जाती रही है। इसके उपरान्त भी इन मक्कारों को अपनी लूट के आगे जनता के आंसू नहीं दिखते हैं।

पोप की बपौती...

पेज 4 से जारी

आदिवासियों की कौम ही बदल दी। यही कारण है खरगोन, झाबुआ, बड़वानी के सुदूर आदिवासी गांवों में हरी आंखों की पीढ़ी नजर आती है यह हाल केवल इंदौर संभाग के आदिवासी बहुल गांवों का ही नहीं वरन जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी जिलों का भी है।

यही हाल पूरे भारत और विश्व में जहां-जहां इस गौरी कौम ने राज किया पूरीदुनिया का यही हाल किया है। यही कारण काले आदिवासी अफ्रीका जंगलों में भी हरी आंखों की पीढ़ी नजर आती है। जहां तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा में धर्म

परिवर्तन की तीव्र गतिविधियों को रोकने के ४० वर्ष पूर्व ही १९६७ में कानून बना दिया गया था, जिसकी उड़ीसा की गरीबी के कारण मखौल उड़ाया जाता रहा है। इससे उन ईसाई मिशनरियों, संस्थाओं पर कोई असर नहीं हुआ और वह धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम देती आ रही है। पिछली दो शताब्दियों से, अब जब ये सच सामने आ रहा है तो हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो पोप की चेती सोनिया उसका चेला कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन भी भारी राजनीतिक कानूनी उठापटक में लगे हैं।

पर मुक्त यौनाचार...

परंतु धरती पर सड़कों की हालत क्या है, इसकी तरफ से आंखें मूढ़ें बंद हैं। जो आजादी के पूर्व सड़कों के लिए आचार संहिता बनाई गई थी, उसका पालन हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। पर हां, सड़कों पर वसूली करने की जोड़तोड़ में दिल्ली से लेकर राष्ट्र के दक्षिणी कोने तक जरूर उठापटक शुरू कर दी गई है। ऐसी शिक्षा किस काम की जो बच्चों को कागजी प्रमाणपत्र बांटकर यह तो बताती है कि स्कूली शिक्षा के नाम पर उसने जीवन का कितना अमूल्य समय जो लौट के कभी नहीं आएगा बर्बाद किया है, परंतु उसे सड़कों पर चलने लायक सभ्य इंसान नहीं बना पाई है। 1832की लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति का भी गुलामों को दी जाने वाली शिक्षा का भी यही उद्देश्य था कि इस देश की जनता को बाबू बनाने लायक ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसे जानवरों की भांति पेट भरने लायक धनार्जन कर कैसे इससे अंग्रेजों की सत्ता चिरस्थायी रह सके, उन्हें पर्याप्त मात्रा में काम करने वाले बाबूओं

और मिस्त्रियों और मजदूरों की फौज हमेशा तैयार मिले, वे कभी सभ्य नागरिकों की तरह जीवन न गुजार सकें। वहीं हश्र कांग्रेसियों के पहले 40 वर्ष के शासन ने इस देश के नागरिकों का भी किया।

स्कूलों में 15 अगस्त मना कर हम हर वर्ष इस देश की भविष्य की पीढ़ियों को क्या सिखा और समझा पा रहे हैं। या केवल झंडा वंदन कर, नाश्ता खिलाकर अपनी और अपने शासकों की या मृत पूर्वजों की जय-जयाकर करवा कर स्वतंत्रता दिवस की इतिश्री कर लेते हैं।

इस राष्ट्र में 120 करोड़ नागरिकों में सबसे बड़ा अभाव है राष्ट्रप्रेम, समर्पण और अपनत्व की भावना का, साथ ही शीर्ष पर बैठे राजनेताओं का खासतौर पर कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों को केवल अपना बैंक बैलेंस दिखता हो, सत्ता सुख की लालसा में लिप्त ये भ्रष्ट जालसाज गिरोह अपने स्वार्थों की खातिर राष्ट्री की जनता के भविष्य को भी दांव पर लगाते हैं, लगाते रहे हैं और रहेंगे।

With Best Compliments on
Dushera & Navratri

Divya Jyoti Industries Limited
600 TDP Solvent Plant
Mfg: Solvent Oil, Doc
Office: 409, Apollo Tower 2, M.G. Road Indore
Ph: 2627336, 2627336
Works: M-1939, Sector II, Industrial Area, Pithampur
Dist. Dhar
Ph: 266390, 266391

जनता व मीडिया का ध्यान परिवर्तन हेतु विस्फोट

महंगाई, परमाणु समझौता, संसद कांड से परेशान कांग्रेस

जयपुर, बंगलोर और अहमदाबाद में किए विस्फोटों और आतंकवादियों की साजिश के पीछे विशुद्ध कांग्रेस का ही हाथ है। यदि स्व. इंदिरा गांधी के इतिहास से लेकर वर्तमान तक देखे तो लगभग 34-35 वर्ष का इतिहास यह सिद्ध करता है, कि कांग्रेस जिसने आतंकवाद को जन्म दिया, पाला पोसा और जड़े पूरे भारत में फैलाई, उन्हें प्रदेश में जमाने में कांग्रेस के दिग्गि दानव भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने पूरा संरक्षण दिया था।

फिर कांग्रेस किस कीबनाई हुई पार्टी है। अंग्रेज ए ओ एम की, जिन अंग्रेजों ने 300 वर्ष जो राज्य किया आखिर भड़काओ, बांटों और राज करो की नीति का ही तो पालन कर रही है, वर्तमान कांग्रेस, उसी का हिस्सा ही है, जयपुर, अहमदाबाद और बंगलोर के बमों के धमाके, निरीहों की नृशंस हत्या, इन धमाकों से कांग्रेस एक तीर से एक साथ मुख्य रूप से 6 कार्य कर रही है।

1. अपने कमीशनखोरी के चलते जनता को जो महंगाई का तोहफा दिया है, उस मुद्दे से ध्यान बंटाने।
2. परमाणु समझौते की आड़ में देश की परमाणु सुरक्षा गिरवी करने, परमाणु ऊर्जा की आड़ में इस धूर्त ने वर्तमान में चल रहे सारे परमाणु ऊर्जा केंद्रों की चाबी अमेरिका रूपी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ को सौंपने उनकी निगरानी सौंपने पुनः परमाणु



ऐतिहासिक अंग्रेजों की पार्टी अंग्रेजों की भड़काओ, बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण कर, अपने पाले आतंकवादियों का उपयोग किया

बम बनाने का भविष्य में साहस न कर सके, भविष्य में परमाणु हमला होने पर अमेरिकी की शरण में जाकर सहायता मांगने के बहाने अमेरिकी सेनाओं को भारत में बुलाने और स्थायी अड्डा बनाने व औपनिवेश बनाने की साजिश से जनता व मीडिया का ध्यान बंटाने के लिए काबुल में पहले भारतीय दूतावास को उड़वाया गया, जब उस पर मीडिया ने ध्यान नहीं दिया, स्वाभाविक है जनता में भी ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा।

संसद में जब यह निश्चित हो गया कि विश्वासमत की परीक्षा होगी, तब से ही जालसाजों का ये टोला

दूसरी राजनीतिक पार्टियों के सांसदों की चरित्रवाली खरीद, बिक्री के दृष्टिकोण से खंगाल कर, खरीद-बिक्री में लग गया था, जो कि वामपंथियों के समर्थन वापसी के आशय पत्र को राष्ट्रपति को सौंपने के साथ ही शुरू कर दिया था। कांग्रेसी धूर्त जालसाजों का इतिहास रहा है ये 1992 में नरसिंंहाराव की सरकार ने शिबू सोरेन को रु. 50 लाख में खरीदा था।

22-7-08 को खरीदे हुए भाजपा के 7 सांसदों, वामपंथियों व अन्य दलों के सांसदों को खरीदी कर धूर्त संग्राम गिरोह ने सरकार को बचाया। जिन तीन भाजपाई सांसदों ने कांग्रेस, सपा गिरोह को सांसद खरीदी के नोटदिखाकर यदि इस गिरोह की सच्चाई राष्ट्र को दिखा दी, तो कांग्रेस गिरोह के देशभर में फैले नीच जालसाज मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए पुनले फूँके, धन्य हो देश को बचने वालों, कमीशन के लिए जनता को नोचने वालों।

जब चारों तरफ कांग्रेस व संग्राम गिरोह की धज्जियां उड़ने लगी तो बंगलोर और अहमदाबाद में धमाके करवाकर फिर जनता और मीडिया का ध्यान परिवर्तन किया गया, ताकि पुराने कुकर्मों से ध्यान हटाया जा सके।

यह आतंकवादी हथकंडा, कांग्रेस गिरोहबाजों का सबसे पुराना शगल है, कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी को जब अंग्रेज देश छोड़कर

जाने लगे तो अपना राज करने का ब्रह्म वाक्य सूत्र विरासत में सौंपकर गई, अंग्रेजों ने भी इस देश के स्वार्थी गुलामों पर इसी ब्रह्म वाक्य के सहारे राज किया, जब आपके लड्डू की पकड़ कमजोर होने लगे तो गोलियां बरसाओ, अब गोलियां का जमाना पुराना पड़ गया है, थोक के भाव में मारने के लिए बमों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मुसलमानों का संगठन सिमी को 1976 के आसपास खड़ा किया गया, पहले यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मुस्लिम छात्रों को संगठन था, जिसे बाद में 30 वर्षों में पूरे देश में फैलाया, अब ये आतंकवाद उन्मुख संगठन से बम धमाके करवाकर कांग्रेस तिहरा खेल करती है, एक तरफ उन संगठनों को बचाकर मुसलमान परस्त होने का दिखावा कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की गहरी होती जड़ों को कमजोर कर हिंदुओं की नजर में मुस्लिमों को तो दूसरी ओर अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए मुस्लिमों का हिंदुओं से अलगाव बनाए रखना चाहती है। तीसरा उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है। वहां की जनता को दहशत देकर समझाती है कि हम नहीं तो तुम चैन से नहीं जी सकोगे।

चौथा वहां की भाजपा की व अन्य दलों की सरकारों को वहां की जनता के साथ पूरे राष्ट्र व विश्व की जनता को ऐसी वीडियो क्लिपिंग दिखाकर उन सरकारों को नकारा, निकमा व असक्षम सिद्ध किया जाता है।

कांग्रेस का, साथ ही उनके जन्मदाता अंग्रेजों की इस देश और दुनिया पर राज करने, राज्य चलाने का ये सबसे नायाब सूत्र है, लड़ाओ, झगडाओ, फूट डालो और ध्यान लूटखसोट, वसूली करते हुए चैन से सत्ता में मौजूद करो। आजादी के 60 वर्षों बाद भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है।

यही कारण था कि सिमी के विरुद्ध उच्च न्यायालय दिल्ली ट्रिब्यूनल ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में प्रतिबंध को गैरकानूनी करार दे दिया। बाद में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर प्रतिबंध लगाया, इसके विपरीत कांग्रेस के ही मुस्लिम वोट परस्तों ने अमरसिंह, ब्योडा मुलायम सिंह ने अपने वोटों की राजनीति केचलते उस प्रतिबंध को हटाने की मांग की, यह कृत्य इन तत्त्वों के चलते हमारी गहरी, लंबी सोच की सच्चाई स्पष्ट करता है।

पैसा दो एसाएएस से आईएएस बनो

रा.प्र.से. के 18 अधिकारी, भा.प्र. सेवा स्तर पर

भोपाल। म.प्र. राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का गजट नोटिफिकेशन कर 84 व 85 के बैच के अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बना दिया गया है। यह खुला खेल अपने विभाग के मंत्रियों की तन, मन से सेवा जी करो, या उनके खानदान या रिश्तेदार बनो। मंत्री उनकी ऐसी उन्नति की सिफारिश करेगा, वे राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बना दिये जाते हैं। बेशक इस खेल में नीचे से ऊपर दिल्ली तक धन और पहुंच चलती है। ऐसा नहीं है कि जो 18 रा.प्र.से. से भा.प्र.से. बनाए गए हैं। बहुत विलक्षण क्षमता, उच्च प्रबंधन या उन्होंने अपनी प्रतिभाओं से प्रदेश में कोई बहुत बड़ा विरला कार्य किया हो, इन सबमें से अधिकांश के भ्रष्टाचारों, वसूली, शासकीय धन की वसूली, खुलेआम कानूनों की धज्जियां उधेड़कर नेताओं, पूंजीपतियों भूमाफियाओं के इशारे पर नाचने, अरबों रु. के धन की हेराफेरी शिकायतों के अनेक मामले लंबित होंगे या धन बांटकर उन पर झाड़ू लगवाई गई होगी, महिलाओं को तो वैसे भी उनकी खूबसूरती, कमसीनता उनकी उन्नति का सबसे बड़ा प्राकृतिक पैमाना है। जिसे हर कदम पर तोला जाता है। बकवाल है, बाकी सब हर जगह आदमी बैठे हैं कानून बनाने वाले और उसका सदुपयोग करने वाले, ऐसा भी नहीं है कि जिनको यह पुरस्कार दिया है, उनकी सबसे बड़ी अयोग्यता ये भी। उसका तो वर्णन स्वयं जनता, पाठक भी जानते हैं। भ्रष्टाचार से न लूटना और न लुटाना।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां यह भी है कि ऐसे अवार्डी अधिकारियों को जो 15 से 20 वर्षों में जिस ढांचे, मानसिकता, कार्यशैली में ढल चुके हैं। सचमुच वो कुछ अच्छा कर पाते हैं नहीं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान इंदौर जिलाधीश राकेश श्रीवास्तव है, जो पदोन्नत रा.प्र. से अधिकारी बन इंदौर जैसा जिला जैसे-तैसे चला पा रहा है। भ्रष्टाचार चारों तरफ न केवल बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, सरकार पर असक्षमता का आरोप लगा है। इसकी गूँज न केवल प्रदेश व देश की राजधानी वरन बीबीसी साइटों पर भी गूँजी है।

ऐसे पदोन्नत भा.प्र.से. अधिकारियों की सबसे बड़ी तमन्ना होती है जिलाधीश बनकर खुलकर भ्रष्टाचार से धन कमाया जाए, उस श्रेणी का तत्काल का उदाहरण पूर्व का धार कलेक्टर रामकिंकर गुप्ता जिसने इस आदिवासी जिले में बैठकर खुलकर चारों तरफ से वसूली की। जब ज्यादा आरोप लगे तो वहां से उठाकर इस इंडियन एब्यूजिंग सर्विस अधिकारी को इंदौर में ही नघावित्रा का आयुक्त पुनर्वास और पुनर्निर्माण बना दिया गया। वैसे ऐसे पदोन्नत अधिकारियों को कही भी बड़ा प्रभार देकर बैठाना, भ्रष्टाचारों का बढ़ावा देना और प्रशासन पर पकड़ ढीली करना है। फिर भी लूटा है, तो लुटाओ और आईएएस बन रतवा और ज्यादा भ्रष्टाचार से कमाओ।



खूब भ्रष्टाचार करो, लूटो और लुटाओ, अच्छे पद, अच्छी कमाई पाओ



61 वर्ष की आजादी के बाद शिक्षा सड़क पर चलना नहीं सिखा पाई पर मुक्त यौनाचार जरूर सिखा रही सरकार

भारत की आजादी को 61 वां. वर्ष शुरू होने जा रहा है, परंतु राष्ट्र की 120 करोड़ जनता में 115 करोड़ को सड़कों पर चलना नहीं सिखा नहीं पाई है, हमारे देश की शिक्षा, सड़कों पर हर वर्ष 5 लाख लोग मर जाते हैं, इसकी परवाह न सरकार को है, न सरकार में बैठे भ्रष्ट नौकरशाहों को, न जनप्रतिनिधियों को न इस देश के तथाकथित कहे जाने वाले बुद्धि जीवियों को।

इसके विपरीत जनता द्वारा चुने गए सांसदों, विधायकों, सरकार में बैठे अधिकारियों के भ्रष्टाचारों को कोई न देखे, कोई अंगुली उठाए इसलिए शासकीय तंत्र स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शैशवास्था में ही बर्बाद करने के लिए अवश्य यौन शिक्षा की पुरजोर वकालात पर तुला है। बेशक इन अक्ल के दुश्मनों की आँखों पर कंडोम निर्माता कंपनियों के निर्माताओं द्वारा बाँटे गए धन का चश्मा भी चढ़ा हुआ है। इन शासक तंत्र में बैठे लोगों के माता-पिताओं ने जब यौन शिक्षा नहीं ली थी, तो इन्हें कैसे पैदा किया होगा बेशक यह आश्चर्य का ही विषय है। संदेह, तो इनके जन्म का भी है कि इन भ्रष्टों की माताओं ने जब यौन शिक्षा प्राप्त नहीं की तो इन्हें कहां से और कैसे पैदा किया होगा या तो सब परख नली की औलादें हैं क्या? जबकि एक तरफ इस राष्ट्र की सड़कों पर मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच रही है, इसकी चिंता किसी को नहीं, हमारी स्कूली शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, यह इसी बात से पता लगती है कि माध्यमिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने वाले भी सड़कों पर न केवल वाहन चालते समय वरन पैदल चलते समय जानवरों से ज्यादा बदतर तरीके से चलते हैं। बीच सड़कों पर खड़े होकर बार-बार हटने के लिए ध्वनि करने पर भी हटने में ये जानवर अपना अपमान समझते हैं। स्वाभाविक है जानवरों को हांकने के लिए बिना लड्डू के हड़काए बिना असर ही नहीं पड़ता, बेशक सड़कों पर 5 लाख से ज्यादा मावों की मौत में वाह चालक ही नहीं सड़कें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रेष्ठ पेज 6 पर

ताकि स्कूलों से ही आने वाली पीढ़ी शासकों के कुकर्मों पर ध्यान न दें

नवरात्रि एवं दशहरे की शुभकामनाएँ

प्रकाश साल्वेश
(A UNIT OF PRAKASH OILS LTD.)
(Manufacture Exporters & Importer)

ऑफिस - 30/एफ-12, घानसत्य चेंबर,
स्नेह नगर, इंदौर-01 इंडिया
फोन - (ऑ.) 464401-02-03, 290555
फैक्स - 95-730-468887
E-mail - pol@satyam.oe.tia

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्प्यू. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.

कम्प्यूटराईजेशन एवं ग्राफिक्स सुनील जोशी, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भावद्वज मो.94256-37958, जबलपुर प्रतिनिधि श्री चंद्रकुमार जैन, 367, सराफा जबलपुर, जबलपुर, इन्दौर फोन-2530859, कार्या. फोन 2309377 मो. 93007-55803